

RNI No.DELHIIN/2011/41355

दिल्ली से प्रकाशित

फरवरी 2026 वर्ष 15 अंक 171 मूल्य 20

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति, विप्लव और अपराध पर केंद्रित पत्रिका



Union Budget 2026

PRIME INDIA
MEDIA HOUSE



PRIME CRIME INDIA

www.primecrimemedia.com

**PSU
TODAY**

www.psuindia.com



NETA INDIA

संपादक: श्री. वि. पी. शर्मा, संपादक: श्री. वि. पी. शर्मा

www.netaindia.com



SERVING EVERY MILE, EVERY DAY FOR A NATION ALWAYS ON THE MOVE



- IndianOil owns and operates 10 group refineries with a refining capacity of 80.75 MMTPA
- Total pipeline length operated by IndianOil is over 20,000 Km
- Pipelines throughput of over 100 Million Metric Tonnes per annum
- Operates over 14,000 Electric Vehicle Charging Stations
- Product sales of over 100 Million Metric Tonnes per annum
- Fueling journeys across the nation with over 40,000 Retail Outlets
- Over 15 Crore kitchens across India trust Indane LPG



नारसिंहर खान
संपादक

वित्त मंत्री ने बताया बजट 2026 में पूरा रोडमैप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक रोडमैप पेश किया। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है। सरकार ने GDP में इसका योगदान 25: तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी तक 20: का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 6 प्रायोरिटी क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इनमें सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, MSME और अर्बन इकॉनमिक क्लस्टर शामिल हैं। सरकार का फोकस डोमेस्टिक इकॉनमी को और मजबूत करने पर है, ताकि देश को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर एंजलॉयमेंट को मजबूती देने के लिए भी सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनका पॉजिटिव असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। इसके साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का ध्यान बना हुआ है। वित्त वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10: की बढ़ोतरी के साथ 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। पिछले कई वर्षों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी की सरकार की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मजबूत ग्रोथ के लिए वह इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश बढ़ाना जारी रखेगी। इसके साथ स्ट्रैटिजिक पहलू को ध्यान में रखकर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ जैसे सेगमेंट को बढ़ावा देने की बात भी सरकार ने कही है। कुछ समय पहले जिस तरह से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी, उसे देखते हुए यह पहल अहम है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और क्लाउड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, जो तेजी से बदलती दुनिया और जियो-पॉलिटिक्स के लिहाज से अहमियत रखते हैं।

बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की 7.4: की अनुमानित GDP ग्रोथ बड़ी बात कही जा सकती है। वित्त वर्ष 2027 में सरकार ने ग्रोथ के साथ रहने का अनुमान लगाया है, जो दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक होगी। इस बजट में ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण को लेकर भी पॉजिटिव घोषणाएं की हैं। वित्त वर्ष 2026 में डेफिसिट जहां ढक्क का 4.4: रहा, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 4.3: का लक्ष्य रखा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कंजम्पशन है। देश की ढक्क में इसका योगदान 60: के करीब है। पिछले साल के बजट में इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स माफ कर दिया था। पिछले फेस्टिव सीजन से पहले सरकार ने GST दरों को तर्कसंगत बनाया था। साथ ही, रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती के हालिया साइकल में 0.75 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इससे भी कंजम्पशन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अगर शेयर बाजार की बात करें तो बजट से उसके हाथ मायूसी लगी है। 2014 सितंबर के बाद से विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। इस बीच, म्यूचुअल फंड, इश्योरेंस कंपनियों में घरेलू निवेशकों का जो पैसा गया है, उससे मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन उनका भरोसा कितने समय तक बना रहेगा, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। छोटे निवेशकों को बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा कर जरूर एक राहत दी गई है, लेकिन इंडिविजुअल प्रमोटर और एंटीटी प्रमोटर के लिए इसकी दरें अलग रखी गई हैं। सवाल है कि कहीं इससे प्रमोटरों की दिलचस्पी बायबैक योजनाएं लाने में कम तो नहीं होगी? मार्केट लंबे समय से अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पक्के संकेत नहीं मिले हैं। अगर यह डील होती है तो इससे मार्केट सेंटीमेंट में जरूर बदलाव आएगा।



स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर बीएसपीएस का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित
मीडिया पार्टनर, प्राइम इंडिया मीडिया हाउस की भूमिका महत्वपूर्ण.. 15

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

RNI No.DELHIIN/2011/41355

DAVP No.0813F27125-025

वर्ष-15, अंक: 171, फरवरी 2026

मूल्य ₹ 20

विदेश प्रतिनिधि

विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख

सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख

अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख

शाहिद अस्करी

दक्षिणांचल ब्यूरो प्रमुख

इमरान खान

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख

योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख

शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख

साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

रानू पाठक

पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी

नरेश कुमार श्रीवास्तव

विशेष संवाददाता

गुफरान खान

प्रमुख संवाददाता

गुलशन अरोड़ा

संपादक
नासिर खान
सलाहकार संपादक
राकेश त्रिपाठी
डॉ. ईशा
अर्चना ज्योती
राजनीतिक संपादक
इंजी.ए पी सिंह
संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रशांत दत्त मिश्रा
कानूनी सलाहकार
डी.बी.गोस्वामी, सलीम खान
(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव
समीर अख्तर



कार समेत गड्ढे में समा गया इंजीनियर, चिल्ला कर मांगता रहा हेल्प ,,,,,,,19



सुनेजा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी ,,,,,,,34

बारामती विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु

संपादकीय

3

भारत की नियति नेतृत्व करना है, संतुलन बनाना नहीं ,,,,,,,24

पीएसयू की खबरें 28

हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर अपने आशियाने बचाने की लड़ाई जीती 40

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की,,,,,, 43

गाड़ी में सफर के दौरान उल्टी आना मतलब मोशन सिकनेस है बीमारी ,,,,,,,45

आरसीबी ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग जीती,,,,,, 49

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो

मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)

मथुरा ब्यूरो

विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो

अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

बलिया ब्यूरो

डॉ.कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),

आरा ब्यूरो

विमलेश कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो

राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस

91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली- 110092

संपादकीय कार्यालय

आर-141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092

मोबाइल-9718647540 Ph.011-46536014

ईमेल-primespectator@gmail.com, primeindia-

mediahouse@gmail.com

वेबसाइट-primeindiamediahouse.com

primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा

ANEJA PRINTERS, C-11, SECTOR-10, NOIDA (UP) से

मुद्रित तथा आर-141/3 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित।

सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टोर के किसी भी रचना के प्रकाशन

से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखक के

निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

प्राइम स्पेक्टोर (मासिक पत्रिका) फरवरी 2026, दिल्ली 5



बजट में छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया



राकेश त्रिपाठी सलाहकार संपादक

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया और 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। हालांकि, बजट में वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति सौदा कर बढ़ाये जाने से शेयर बाजार लगभग दो प्रतिशत तक लुढ़क गया था। बीएसई सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 495 अंक की गिरावट आई थी। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट में बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा पेश की गई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, इसके बावजूद राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया गया और राजकोषीय मजबूती तथा बुनियादी ढांचे पर जोर बनाया रखा

गया है। सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए लोकसभा में अपने लगभग 90 मिनट के भाषण में 'विकसित भारत' के लिए प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ भविष्य की प्रौद्योगिकियों को पारंपरिक उद्योगों के साथ एकीकृत करने की योजनाएं शामिल हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाये रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया जो 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सात 'हाई-स्पीड' रेल गलियारा बनाने की योजना भी शामिल है, जबकि रक्षा व्यय लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे तनाव के बीच उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों... औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। हालांकि, व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से कर और प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के

लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा भारत से वैश्विक डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 20 वर्षों के लिए कर छूट देने के साथ ही विदेशी 'क्लाउड' कंपनियों की संबंधित इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डेटा सेंटर सेवाओं की लागत पर 15 प्रतिशत की छूट देना है। इस कदम से वैश्विक क्लाउड कंपनियों को कर संबंधी निश्चितता और परिचालन दक्षता मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने छूटों को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है। साथ ही श्वैगैजर् नियमों में ढील दी है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के चौपियन तैयार करने के लिए 10,000 करोड़



रुपये का एसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्सा. हन प्रदान करने की बात कही गयी है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट एक जटिल परिस्थितियों में आया है। हालांकि, घरेलू मांग बनी हुई है और मुद्रास्फीति हाल के उच्चस्तर से कम हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर तनाव, अस्थिर जिंस कीमतों सहित वैश्विक अनिश्चितताएं भविष्य के परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं। घरेलू मोर्चे पर, सरकार पर राजकोषीय घाटे को काबू में रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने को लेकर दबाव है। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आज हम ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद दोनों खतरे में हैं और संसाधनों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है। नई प्रौद्योगिकियां उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि देश समावेशी लक्ष्यों को संतुलित करते हुए विकसित भारत की दिशा में भरोसे के साथ कदम बढ़ाना जारी रखेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं वाली एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से एकीकृत रहना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि और इसके लिए सरकार राजकोषीय मजबूती पर प्राथमिकता के आधार पर काम करती रहेगी, जिसका लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में ऋण-जीडीपी अनुपात को 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करना और राजकोषीय घाटे को चालू वर्ष के 4.4 प्रतिशत से घटाकर 4.3 प्रतिशत करना है। सीतारमण ने बजट पेश होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में एसटीटी में वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि यह छोटे निवेशकों को वायदा एवं विकल्प खंड में सट्टेबाजी के कारोबार से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। सीतारमण कहा कि इस तीन स्तरीय दृष्टिकोण के लिए एक अनुकूल परिवेश की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता संरचनात्मक सुधारों की गति को बनाए रखना है, जो भविष्या. 'न्मुखी हों। दूसरी, बचत जुटाने, पूंजी का कुशलतापूर्वक आवंटन करने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तीसरा, एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां बेहतर राजकाज के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिता की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। विकसित भारत के लिए श्रबैकिंग को तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन में ढील देने और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने पर काम कर रही है। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला एक नया माल दुलाई गलियारा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (उत्तर पश्चिम)

8 **प्राइम स्पेक्टेटर (मासिक पत्रिका) फरवरी 2026, दिल्ली**

चालू किए जाएंगे, एक तटीय माल दुलाई प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और समुद्री विमानों के विनिर्माण के लिए प्रोत्सा. हन प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा के लिए, शर्कबर्न कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले पांच साल में 20,000 करोड़ रुपये के व्यय की घोषणा की गई। सरकार पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल गलियारों का विकास करेगी। कर संबंधी उपायों में जुमाने और अभियोजन प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना, अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करने वाले सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट और शराब, कबाड़ और खनिजों जैसी विशिष्ट वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दर को दो प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाना और तेंदू पत्तों पर इसे पांच प्रतिशत से घटा. कर दो प्रतिशत करना शामिल है। बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी गई मूल सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया गया है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के मामले में यही किया गया है। सात और दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओंऔषधियों और भोजन के शुल्क-मुक्त व्यक्तिगत आयात की अनुमति दी गई है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों और वापस लौटे प्रवासी भारतीयों जैसे छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए, उन्होंने एक बार की छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

कैंसर की दवाएं, माइक्रोवेव ओवन होंगे सस्ते, आयातित छाते, एटीएम महंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की। इससे 17 कैंसर की दवाओं के साथ-साथ सात दुर्लभ बीमारियों के लिए विशेष चिकित्सकीय आवश्यकताओं वाली दवाओं एवं खाद्य पदार्थों के साथ-सा. थ माइक्रोवेव ओवन में उपयोग होने वाले कलपुर्जों की कीमत भी कम हो जाएगी। आयातित सस्ते छाते, एटीएमकैश डिस्पेंसर जैसी कुछ वस्तुएं मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण महंगी हो जाएंगी।

सस्ती होने वाली वस्तुएं-

कैंसर की दवाएं

सात दुर्लभ बीमारियों से संबंधित विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दवाएं, औषधियां



और खाद्य पदार्थ

व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाएं
माइक्रोवेव ओवन के प्रमुख कलपुर्जे
विमान के इंजन सहित कलपुर्जे
सोलर ग्लास के कलपुर्जे
परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आया-
तित सामान

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान

महंगी होने वाली वस्तुएं व सेवाएं—

कम लागत वाले आयातित छाते
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एटीएमकैश डिस्पेंसर मशीन और उसके
कलपुर्जे
विदेशी लोगों के लिए फिल्म और प्रसारण
उपकरण
चिड़ियाघर में बाहर से जानवर व पक्षी लाना
अमोनियम फॉस्फेटनाइट्रो-फॉस्फेट उर्वरक
और नेपथा जैसे उर्वरक
कॉफी भूने, बनाने या बेचने की मशीन
अरंडी खल

—आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब
संपत्ति निर्माण से पहले का ब्याज भी शामिल
करने का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया
गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के
मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिल-
ने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर
कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या
निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शा-
मिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए
सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा
22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल
2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह
ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी
रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर
अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से
होने वाली आय के मामले में मिलने वाली

कटौतियों से संबंधित है।

**दिल्ली को वित्तवर्ष 2026-27 में भी गृह
मंत्रालय से 1348 करोड़ रुपये मिलेंगे**

केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के लिए
आवंटन पिछले वर्ष के समान ही 1,348
करोड़ रुपये है। यह दिल्ली में नयी भाजपा
सरकार के तहत पहला बजट है। मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए
कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के
श्विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार
करने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय
बजट 2026-27 के अनुसार, केंद्रीय गृह
मंत्रालय से दिल्ली को कुल 1348.01 करोड़
रुपये आवंटित होंगे, जिनमें राजस्व मद के
तहत 968.01 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय
मद के तहत 380 करोड़ रुपये का आवंटन
शामिल हैं। ये आंकड़े 2025-26 वित्तीय वर्ष
के बजट अनुमानों को दर्शाते हैं।

**बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय को 10
प्रतिशत अधिक आवंटन**

सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27
में कई कदमों की घोषणा करके स्वास्थ्य अव-
संरचना, मेडिकल शिक्षा और फार्मा सेक्टर
के आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा
दिया। इन कदमों में भारत को सहायक
स्वास्थ्य पेशेवरों और बायोफार्मा निर्माण के
लिए वैश्विक हब बनाने के प्रयास भी शा-
मिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि
केंद्र सरकार के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय
के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,06,530.42 करोड़
रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष
2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में
लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
बढ़ाए गए आवंटन में स्वास्थ्य अनुसंधान
विभाग (डीएचआर) के लिए 4,821.21 करोड़
रुपये की मजबूत वित्तीय सहायता भी शामिल

है, जो वित्त वर्ष 2014-15 के स्वास्थ्य बजट
की तुलना में कुल मिलाकर 194 प्रतिशत से
अधिक की वृद्धि है।

बजट में सात क्षेत्रों में विनिर्माण

गतिविधियों पर प्रोत्साहन की घोषणा

देश की विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत
करने के लिए रविवार को पेश बजट में सात
श्रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों पर विशेष
ध्यान देने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें दुर्लभ
पृथ्वी चुंबक, वस्त्र, सेमीकंडक्टर और कंटेनर
जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट भाषण
में श्विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए जिन तीन कर्तव्यों की घोषणा
की, उनमें विनिर्माण का विस्तार करना
भी एक प्रमुख स्तंभ है। सरकार ने औषधि,
सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा, दुर्लभ
पृथ्वी खनिज, रसायन, पूंजीगत उत्पादन
और वस्त्र जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों की पह-
चान की है। बजट 2026-27 में विनिर्माण
को केंद्र में रखा गया है, जिसका अंदाजा
इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे
बजट भाषण में श्विनिर्माण शब्द का 24 बार
उल्लेख किया गया। बजट में बायोफार्मा और
कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए
कुल 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया
गया है, जिसमें बायोफार्मा शक्ति योजना के
तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये
खर्च होंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
उपकरण, सामग्री और स्वदेशी बौद्धिक संपदा
विकास पर केंद्रित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कल-
पुर्जा विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर
40,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके
अलावा दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों, रसायन, पूंजीगत
वस्तु, वस्त्र, खेल सामग्री और समुद्री विमानों
के विनिर्माण को भी बजट में समर्थन दिया
गया है।

**महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी है
आम बजट : पीएम नरेंद्र मोदी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आम
बजट 2026-27 को महत्वाकांक्षी और
भविष्योन्मुखी बताया। उन्होंने इस बात
पर जोर दिया कि यह भारत की वैश्विक
भूमिका को और मजबूत करेगा, क्योंकि देश
के 140 करोड़ नागरिक इसके सबसे तेजी
से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं
और राष्ट्र जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे
बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकलि-
पत है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण की ओर से बजट पेश किए जाने
के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने



संबोधन में मोदी ने कहा

कि यह एक अनूठा बजट है, जिसमें राज. कोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही साथ उच्च पूंजीगत व्यय एवं उच्च विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा, श्रृंखला बजट भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से मजबूत करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं, और राष्ट्र जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से हाल में किए गए प्रमुख व्यापार समझौतों का उद्देश्य देश के युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इस बजट में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मोदी ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है और देश की महिलाओं की सशक्त भावना को दर्शाता है। यह बजट महत्वाकांक्षी है और देश की आकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और उनकी टीम को गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित भविष्योन्मुखी और संवेदनशील बजट पेश करने के लिए धन्यवाद दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीतारमण ने एक महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 तक श्विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की रूपांतरण एक्सप्रेस पर

नयी ऊर्जा

और नयी गति प्रदान करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट विश्वास आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट श्रमेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा पेश करता है। मोदी ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को मजबूत करने, वस्त्र क्षेत्र में नयी योजनाएं, हाई-टेक उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन देने और अग्रणी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तैयार करने जैसे अभूतपूर्व समर्थन दूरदर्शी हैं और राष्ट्र की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों समेत एमएसएमई को दिया गया समर्थन उन्हें स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक विकसित होने में सक्षम बनाएगा। मोदी ने कहा कि यह दूरदर्शी बजट है और देश की वर्तमान और भविष्य, दोनों ती जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें एक समर्पित माल दुलाई गलियारा, देशभर में जलमार्गों का विस्तार, एक हाई-स्पीड रेल गलियारा, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देना और शहरों के लिए मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करने के वास्ते नगरपालिका बांड को बढ़ावा देना शामिल है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी उपाय श्विकसित भारत की ओर यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी

उसके नागरिक होते हैं और हाल के वर्षों में सरकार ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौशल, व्यापकता और स्थिरता को मजबूत करने के लिए लगतार प्रयास किए जा रहे हैं।

बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने श्रृंखला पर पोस्ट किया कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

सरकार के पास कोई नीति, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई तथा किसानों की भी उपेक्षा हुई है। खरगे ने श्रृंखला पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार के पास अब नए विचारों की कमी दिखती है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। मिशन मोड अब चौलेंज रूट बन गया है। सुधार एक्सप्रेस शायद ही कभी किसी सुधार जंक्शन पर रुकती है। उन्होंने दावा किया कि अब कोई नीति-दृष्टि नहीं है और कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान आज भी सार्थक कल्याणकारी समर्थन या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के दौर से भी आगे



निकल चुकी है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई सहायता दी गई है। खरगे के अनुसार, वित्त आयोग की सिफारिशों का और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे भी गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिखती तथा संघवाद इसकी बलि बन गया है। उन्होंने कई अन्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बजट कोई समाधान नहीं देता। नीति के अभाव को छिपाने के लिए इसमें नारा तक नहीं है।

केंद्रीय बजट पर मुस्लिम संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया

केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए वित्तीय प्रावधान बढ़ाए जाने पर मुस्लिम संगठनों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने पिछली बार के मुकाबले इस बार केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 1240 करोड़ रुपये की वृद्धि किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के मुकाबले वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 1240 करोड़ रुपये अधिक का अनुमान प्रस्तुत किया है, जो उत्साह जनक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बजट का वाजिब फायदा शिया समुदाय को अक्सर नहीं मिलता है और सरकार को इस पर गौर करके कोई ऐसा तंत्र लागू करना चाहिए जिससे बजट का उचित लाभ शिया समुदाय को भी मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद

रशीद फरंगी महली ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए बजट में जितना इजाफा किया जाना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कई बार से अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति और अन्य मदों का बजट जिस तरह से कम किया गया या खत्म किया गया, उस हिसाब से इस बार बजट में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मौलाना रशीद ने कहा कि अल्पसंख्यकों के रोजगार, उनकी उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रशिक्षण के लिए और भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाने की जरूरत है, जिसके लिए बजट से और भी ज्यादा उम्मीदें थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए बजट में लगभग 832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है जो पिछली बार के संशोधित अनुमान से लगभग 1240 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि इस बजट का इस्तेमाल बेहतर योजना बनाकर किया जाए ताकि इसका पूरा लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को मिल सके। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट इस बार काफी बढ़ाया है जिससे अल्पसंख्यकों विशेष कर मुस्लिम समाज के

लोगों को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कुमार बासित अली ने कहा कि इस बार केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तुत किया गया है जो सकारात्मक सोच को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। पिछले बजट में मंत्रालय का बजट अनुमान 3,350 करोड़ रुपये था, हालांकि संशोधित अनुमान 2,160.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बार सीतारमण द्वारा किये गये बजट आवंटन में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए 831.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय के तहत केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 1,197.97 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की गति तेज करेगा : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नये दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने शक्सर पर पोस्ट किया कि विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है, ताकि वे उन सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने सरकार द्वारा राजकोषीय विवेक के साथ विकास और प्रगति को रफ्तार देने की प्रतिबद्धता पर जबर्दस्त तरीके से मुहर लगाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि बजट राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए श्रोडमैप पेश करता है।

डेटा सेंटर क्षेत्र में 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद: अश्विनी वैष्णव
सरकार को उम्मीद है कि देश में डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश 200 अरब डॉलर को पार



कर जाएगा और इस पारिस्थितिकी तंत्र को बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र को अब तक 90 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें से 70 अरब डॉलर का निवेश निर्माण चरण में पहुंच चुका है। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, परमाणु ऊर्जा का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगी, जो एआई अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमें डेटा सेंटर में 200 अरब डॉलर तक के निवेश की उम्मीद है। 15 अक्टूबर-दिसंबर के दौरान, गूगल ने 15 अरब डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 अरब डॉलर, अमेजन ने 35 अरब डॉलर और डिजिटल कनेक्शन ने भारत में डेटा सेंटर सहित एआई बुनियादी ढांचे में 11 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव दिया है।

बजट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए

कई उपाय: वाणिज्य सचिव

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 में कई उपाय की घोषणा की गई है, जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों में विनिर्माण और कारोबारी सुगमता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना शामिल है। अग्रवाल ने कहा कि बजट में श्रम-प्रधान और उच्च-तकनीकी वाले, दोनों क्षेत्रों के लिए उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक और कारोबारी सुगमता पर ध्यान देने से अनुपालन का बोझ कम होगा और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया, यह एक बेहतरीन बजट है, जो विनिर्माण, कारोबारी सुगमता और नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देता है। इससे व्यापार विविधीकरण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फार्मा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, कपड़ा और सेमीकंडक्टर के संबंध में की गई घोषणाएं देश के निर्यात को और बढ़ावा देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात

का प्रस्ताव रखा। यह कदम उन चमड़ा निर्यातकों को राहत देगा, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के कारण दबाव में हैं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, श्रम निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले कुछ खास कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। अग्रवाल ने कहा कि इससे इन क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

बजट में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से कृषि क्षेत्र खुश, खाद्य तेल क्षेत्र निराश

कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 का बड़े पैमाने पर स्वागत किया जिसमें 20,000 पशु चिकित्सा पेशेवरों को जोड़ने, शुल्क में कटौती के जरिये अपतटीय मछली पकड़ने को बढ़ावा देने तथा काजू एवं अखरोट जैसी महंगी फसलों को समर्थन करने की सरकार की योजनाओं की तारीफ की गई। हालांकि, खाद्य तेल क्षेत्र ने आयात पर निर्भरता कम करने के उपायों की कमी पर निराशा जताई। उद्योग के लोगों ने कहा कि बजट प्रौद्योगिकी पर आधारित, उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने वाली खेती की ओर एक रणनीतिक बदलाव दिखाता है, जिसमें नए एआई मंच, बढ़ा हुआ मवेशी चिकित्सा बुनियादी ढांचा और मत्स्य पालन, डेयरी और खास फसलों के लिए लक्षित समर्थन शामिल है, जिसका मकसद खेती की आय और निर्यात प्रतिस्पर्धिता ताकत बढ़ाना है। आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन शोध संस्थान के निदेशक, डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज ने कहा कि बजट जरूरी शुल्क छूट के जरिये अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देकर श्वू इकॉनमीश के लिए एक रणनीतिक ढांचे की पेशकश करता है। उन्होंने बताया कि इस कदम से आसपास के संसाधनों पर पारिस्थितिकीय दबाव कम होने की उम्मीद है, साथ ही भारतीय समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी होगी। समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकार (एमपीईडीए) के निदेशक, डॉ. राम मोहन एम के ने कहा कि खुले समुद्र में समुद्री मछली पकड़ने पर शुल्क में छूट से निवेश बढ़ेगा और संसाधनों का इस्तेमाल होगा। हेरिटेज फूड की कार्यकारी निदेशक, ब्राह्मणी नारा ने नए कॉलेजों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और पैरा-वेट

नेटवर्क के जरिये 20,000 पेशेवरों द्वारा पशु चिकित्सा क्षमता बढ़ाने का स्वागत किया।

सरकार को 2026-27 में आरबीआई, बैंकों से 3.16 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद

केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थानों से लाभांश और अधिशेष के रूप में 3.16 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3.75 प्रतिशत अधिक है। संसद में प्रस्तुत संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को लगभग 3.05 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जो फरवरी, 2025 में पेश किए गए आम बजट में 2.56 लाख करोड़ रुपये था। बजट दस्तावेजों में यह भी बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य निवेश से मिलने वाला लाभांश 75,000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो चालू वित्त वर्ष के बजट में 71,000 करोड़ रुपये था।

सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए 2026-27 में कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा, श्रृंखला राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा, श्रृंखला बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। श्रृंखला ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई

ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे।

पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप, हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास की घोषणा

केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा की गई है। इनमें प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना, हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शकटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करना तथा शिक्षा के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टी.एस.एस) की दर को घटाकर दो प्रतिशत करना शामिल है। इस क्षेत्र के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल हैं। लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। सीतारमण ने देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की।

उद्योग जगत ने आम बजट को बताया भरोसा बढ़ाने वाला

केंद्रीय बजट 2026-27 को भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बनर्जी ने राजकोषीय अनुशासन पर सरकार के जोर का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भारत के आर्थिक प्रबंधन में भरोसा बढ़ाता

है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाना निजी निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।

बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3,400 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान

केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3,400 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजटीय अनुमान से 50 करोड़ रुपये और 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 1,240 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। पिछले बजट में मंत्रालय का बजट अनुमान 3,350 करोड़ रुपये था, हालांकि संशोधित अनुमान 2,160.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बार सीतारमण द्वारा किये गये बजट आवंटन में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए 831.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 1,197.97 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

यह बजट प्रधानमंत्री मोदी में लोगों के अटूट भरोसे को दर्शाता है: भाजपा अध्यक्ष नवीन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि रविवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक अगला कदम है, साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है। नवीन ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट के हर पहलू में साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को साफ तौर पर दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में नौवीं बार बजट पेश किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे है, साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज

के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से बजट का स्वागत करता हूँ। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह श्रयुवा केंद्रित बजटश्र है क्योंकि यह उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। उन्होंने कहा, श्रसेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के जरिए बनाई गई मजबूत समर्थन प्रणाली साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार रोजगार के नए मौके पैदा करने पर कितना गंभीर है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बजट में महात्मा गांधी के श्राम स्वराज के दृष्टिकोण को भी साफ तौर पर दिखाया गया है।

बजटआर्थिक, राजनीतिकदूरदर्शिताकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता: चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनका भाषण तथा बजट आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कटाक्ष भी किया कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि आज संसद में वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ सुनने को मिला उससे अर्थशास्त्र का हर छात्र अवश्य ही स्तब्ध रह गया होगा। बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए, जिनका जिक्र कुछ दिन पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे संदेह है कि सरकार और वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा भी है या नहीं। अगर उन्होंने पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से दरकिनार करने का फैसला कर लिया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (लगभग 30 प्रतिशत) का कम स्तर और निजी क्षेत्र की निवेश करने में हिचकिचाहट, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को लेकर अनिश्चित दृष्टिकोण और पिछले कई महीनों से विदेशी निवेश का बाहर जाना, राजकोषीय समेकन की बेहद धीमी गति, राजकोषीय घाटा बढ़ना, लाखों एमएसएमई का बंद होना, युवाओं में बेरोजगारी, बढ़ता शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों (नगर पालिकाओं और नगर निगमों)

में बिगड़ता बुनियादी ढांचे जैसी कई चुनौतियां हैं। चिदंबरम ने दावा किया कि इनमें से किसी भी मुद्दे का वित्त मंत्री के भाषण में कोई समाधान पेश नहीं किया गया। उनके अनुसार, लेखा जोखा मानकों से भी देखें तो 2025-26 में वित्त प्रबंधन का यह एक बेहद खराब लेखा-जोखा था। चिदंबरम ने कहा कि राजस्व प्राप्तियां 78,086 करोड़ रुपये कम रहीं, कुल व्यय 1,00,503 करोड़ रुपये कम रहा। राजस्व व्यय 75,168 करोड़ रुपये कम रहा और पूंजीगत व्यय में 1,44,376 करोड़ रुपये की कटौती की गई (केंद्र 25,335 करोड़ रुपये और राज्य 1,19,041 करोड़ रुपये)। इस दयनीय प्रदर्शन की व्याख्या करने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि वास्तव में, केंद्र का पूंजीगत व्यय 2024-25 में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 3.1 प्रतिशत रह गया है। चिदंबरम ने कहा कि बजट भाषण की सबसे गंभीर आलोचना यह है कि वित्त मंत्री योजनाओं, कार्यक्रमों, मिशन, संस्थानों, पहल, कोष, समितियों आदि की संख्या बढ़ाते जाने से थकती नहीं हैं।

थरुर का वित्त मंत्री पर तंज: लगता है गेंद खेलने से चूक गई और स्टंप हो गई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरुर ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर क्रिकेट शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया कि वह श्रगेंद खेलने से चूक गई और स्टंप हो गई। कांग्रेस सांसद थरुर ने एक साक्षात्कार में कहा कि सीतारमण के बजट भाषण में विशेष बातें कम थीं और इसमें समग्र दृष्टिकोण का पूरी तरह अभाव था। तिरुवनंतपुरम से लो. कसभा सदस्य थरुर ने कहा कि इस बजट में खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। थरुर ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न अब भी रोजगार का है, और बजट भाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रोजगार कैसे पैदा किया जाएगा। जब थरुर से पूछा गया कि क्या वित्त मंत्री ने श्रानदार शॉट लगाया हैश्र या श्रपूरी तरह से चूक गई और स्टंप हो गईश्र, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह स्टंप हुई हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गेंद चूक गई हैं। एक-दो जगहों पर बल्ले का किनारा लगा हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक यह पक्का नहीं लग रहा है कि बल्ले के बीच से कोई शॉट लगा हो।

केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गयी है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। इस कोष का इस्तेमाल नियमित खर्चों और विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में एक आदर्श यातायात प्रणाली का विकास और एक उन्नत संचार नेटवर्क का विकास शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,931.66 करोड़ रुपये था, जिसे आगामी वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 12,503.65 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, खासकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और विकास, खेलकूद, विदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर छूट आदि।

आम बजट देश में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला : केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को आए आम बजट में रोजगार बढ़ाने, महंगाई कम करने, विदेशों से काला धन लाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया और इस बजट को निराशाजनक बताया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आम बजट देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, लेकिन इस बजट में रोजगार देने का कोई ब्लू प्रिंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने गोवा राज्य की अनदेखी करने पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश का आम बजट आ गया है। पहली चीज तो यह है कि इस बजट में गोवा के लिए कुछ नहीं है। पूरे बजट में गोवा शब्द ही नहीं है। केंद्र सरकार गोवा को भूल गई है और गोवा के लोगों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह बजट महंगाई बढ़ाएगा। यह बेरोजगारी और पैदा करेगा। आज बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी और महंगाई की है, लेकिन रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। यह केवल और केवल महंगाई बढ़ाने वाला बजट है।

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर बीएसपीएस का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित

मीडिया पार्टनर, प्राइम इंडिया मीडिया हाउस की भूमिका महत्वपूर्ण



नई दिल्ली। स्वामी विवेकानंद के 164 जन्मदिन के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आज की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सेमिनार में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल बतौर और मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (बीएसपीएस) ने किया। आयोजन में बीएसपीएस के मीडिया पार्टनर प्राइम इंडिया मीडिया हाउस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव व सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं में सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप की भावना काफी बढ़ी है। उनकी सरकार अब तो हर महीने बाकायदा युवाओं के कामकाज का मूल्यांकन भी कर रही है ताकि हमारा देश मोदी मिशन 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। इसके अलावा श्री अग्रवाल ने युवाओं जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। वहीं बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने इस मौके पर देशभर में पहले अपने संगठन के सिलसिले में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के प्रयास से ही पत्रकारों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि की शुरुआत की। और हाल ही में पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर एक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। जिसमें इस कमेटी के आने के बाद ही पत्रकार के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन पत्रकारों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। कार्यक्रम के वरिष्ठ वक्ता जाने माने पत्रकार विवेक शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों को रोजगार जाने से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी आगे आकर कदम उठाना चाहिए। वहीं पत्रकार विवेक शुक्ला ने कहा कि आज के पत्रकार को आधुनिक तकनीकियों से लेस होना होगा तभी वह आगे बढ़ पाएगा। जब हम आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे तभी हम वर्तमान के साथ चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज का पत्रकार संस्थाओं पर निर्भर न रहकर अपने दम पर भी न सिर्फ अपना रोजगार पा सकता है बल्कि कई और लोगों को रोजगार दे सकता है। वहीं कार्यक्रम में पत्रकार विनीता यादव ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ एक ऐसा संघ है जो देश भर के पत्रकारों को एक संरक्षक के तौर पर काम रहा है। इसके अध्यक्ष संजय सिंह ने लगातार पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हाल में विमोचित हुई अपनी एक पुस्तक वाइफ स्वॉपिंग का जिक्र भी किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों को बीएसपीएस के पदाधिकारियों ने शील्ड, अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में प्राइम इंडिया मीडिया हाउस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक मीडिया पार्टनर के रूप में कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बीएसपीएस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन पांडे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नासिर खान, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष नीरज कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबुल राज के अलावा गोरखपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष मा. रकंडे मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला एवं विनीता यादव के साथ-साथ तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की।

कौन थे स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। वे एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई। उनके पिता, विश्वनाथ दत्त, एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद का पालन-पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ, जो धार्मिकता, अध्यात्म, और उच्च संस्कारों से भरा हुआ था। उनके माता-पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए और छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद में गहरी धार्मिक भावना और अध्ययन की इच्छा देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ कलकत्ता के प्रिंस बयल स्कूल से हुआ था, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा की नींव रखी। वे एक मेधावी छात्र थे, और उनके विद्यालय में हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और दर्शनशास्त्र में रुचि रखते थे। उनकी धार्मिकता के प्रति रुचि और ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वे अक्सर अपने गुरु से या अपने साथियों से जीवन के गूढ़ सवालों के बारे में सवाल पूछा करते थे। उनका यह जिज्ञासा उन्हें जल्द ही एक खोजी और ज्ञानवर्धक मार्ग पर ले गई। स्वामी विवेकानंद का मननशील और विचारशील स्वभाव था, जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। वे एक समय में दो अलग-अलग तरह की मानसिकता रखते थे — एक तरफ वे धार्मिक गुरुओं की शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते थे, तो दूसरी ओर वे पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले, तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली और उनके दर्शन को आत्मसात किया। यही वह समय था जब वे अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर स्पष्ट रूप से अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद के बचपन और युवावस्था में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति और समाज की बेहतरी के लिए एक जुनून और प्रतिबद्धता पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिनों में ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उनका यह मानना था कि भारतीय समाज को पुनः जागृत करने और उसे अपनी पुरानी महानता की ओर वापस लौटने की जरूरत थी।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टर डेस्क

नरवणे के संस्मरण को लेकर राहुल ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर साधा निशाना

सरकार बोली सदन को गुमराह कर रहे हैं राहुल



शाहिद अस्करी
पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार फरवरी को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि किताब की बातें सामने आईं तो देश को भाजपा के दोनों प्रमुख नेताओं की असलियत पता चल जाएगी और यह भी मालूम पड़ जाएगा कि चीन के सामने 56 इंच की छाती का क्या हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भा. रतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वह काल्पनिक बातें करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कई बार यह मुद्दा उठाए जाने की कोशिश करने पर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला

तथा कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में गतिरोध बने रहने पर सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद शाम चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलने नहीं दिया जा रहा है और सरकार इस बात से डरी हुई है कि यदि पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक की बातें सामने आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सिंह की असलियत देश को पता चल जाएगी। राहुल गांधी का यह भी कहना था कि देश को यह भी पता चलेगा कि जब चीन के सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो “56 इंच की छाती” का क्या हुआ था। उन्होंने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है। वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में राहुल ने श्पेक्स पर लिखा कि पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने

पर्दाफाश के डर से वे मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की पुस्तक श्फोर स्टार्स ऑफ़ डे. स्टिनी’ के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है। इस विषय पर कार्यवा. ही पहली बार स्थगित होने से पहले जब लोकसभा में गतिरोध जारी था तब

प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे। जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा कि आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात रखना चाहते हैं। सदन में लगातार गतिरोध बने रहने पर बिरला ने लोकसभा की बैठक अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की बैठक पुनरु शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर इसी मुद्दे को रखने का प्रयास किया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। कांग्रेस नेता की बातों का विरोध करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, श्रृंखला पूरी तरह काल्पनिक बातें हैं, नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस विषय पर बोले जाने से रोका जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि आप (राहुल) देश को नीचा दिखाकर क्या कहना चाहते हैं, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई स्रोत नहीं है, आप ऐसी कोई बात मत बोलिए, जिससे सेना का मनोबल गिरे। श्रृंखला सदन में गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने तीन बजकर आठ मिनट पर सभा की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे फिर से शुरू होने पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने व्यवस्था का हवाला देते हुए राहुल गांधी से अपील की कि वह अपनी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण



पर रखें। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से उसी विषय को उठाने का प्रयास किया।

सदन में गतिरोध बने रहने पर पाल ने शाम चार बजकर 10 मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में रीजीजू ने कहा कि “भारत विरोधी तत्वों” की भाषा बोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था, “राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार या संसद में गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।” कांग्रेस के संगठन महासचिव केंसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने नियमों का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा का कहना था कि राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं वो एक पुस्तक में है और उसके अंश एक पत्रिका में छपे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों डर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश

यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय उठाना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए।

राहुल ने संसद की गरिमा कम की: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले की अवहेलना करते हुए सदन में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर अपने झूठे आरोपों से संसद की गरिमा को कम किया और भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया। लोकसभा में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित श्रृंखला को उद्धृत करने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। हालांकि, रक्षा मंत्री और अन्य भाजपा सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और कांग्रेस नेता पर सदन को श्रृंखला करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर गतिरोध के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि यह “जानबूझकर” और भारत को बदनाम करने तथा देश की सेना का मनोबल गिराने की



“सोची-समझी साजिश” का हिस्सा था। रीजीजू ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें और भारत-विरोधी तत्वों की भाषा न बोलें। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक हथियार न बनाएं। उन्होंने कांग्रेस नेता से यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस सरकार के दौरान भारत के हिस्से को चीन के हाथों गंवाने पर देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संसद में श्दुश्मनों की भाषा बोल रहे थे। सिंह ने संसद भवन परिसर में ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि वह सदन के अंदर, देश के अंदर और विदेश में दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। यह सोनिया गांधी का घर नहीं है। यह लोकसभा है। यह लोकसभा अध्यक्ष की दी गई व्यवस्था से और नियम पुस्तिका में बताए गए नियमों के अनुसार चलेगी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के बावजूद इस मुद्दे पर बोलने पर अड़े रहने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की। उन्होंने श्वेक्स पर कहा कि यह इन जिद्दी राहुल गांधी के वैचारिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती से देश और भारतीय सेना की छवि खराब करने के बाद, राहुल गांधी ने अब संसद के अंदर भी देश को बदनाम करना और भारत के बहादुर सैनिकों का अपमान करना शुरू कर दिया है। बलूनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने न केवल संसद की गरिमा को कम किया, बल्कि अपने लगातार झूठे आरोपों और गुमराह करने वाले बयानों से बहादुर भारतीय सैनिकों का मनोबल भी गिराया। भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि उस किताब में क्या लिखा है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है? इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मना किए जाने के बावजूद, सदन में बार-बार उसी निराधार दावे को दोहराना न केवल आसन का अपमान है, बल्कि देश और सशस्त्र बलों का भी अपमान है। बलूनी ने कहा कि यह श्वेबेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा



अध्यक्ष के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद गांधी बिना किसी सबूत के सदन के पटल से देश को गुमराह कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कई मंचों पर बताया है कि कैसे हमारे बहादुर सैनिकों ने डोकलाम में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने निचले सदन में राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा की और आरोप लगाया कि सेना को बदनाम करना और सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करना कांग्रेस नेता की यह आदत बन गई है। प्रसाद ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, पूर्व सेना प्रमुख ने कई न्यूज चैनलों को बताया है कि भारतीय सैनिकों ने गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने यह भी कहा कि गलवान में भारत की एक इंच भी जमीन नहीं गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों का हवाला नहीं दे रहे, बल्कि एक ऐसी किताब पर राजनीति कर रहे हैं, जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी, राजद सांसद मनोज झा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने गांधी का समर्थन किया।

भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा, नरवणे की पुस्तक से मोदी सरकार के मंत्री क्यों घबराए हुए हैं: खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रवाद को झूठा

करार दिया और सवाल किया कि पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार के मंत्री घबरा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से ऐसे बच रही है जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि आरएसएस-भाजपा की वैचारिक आधारशिला ही तथ्यों को छिपाने पर टिकी है, तभी ये कायर मोदी सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से ऐसे बच रही है जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब में ऐसा क्या लिखा है जिससे मोदी सरकार के बड़े-बड़े मंत्री घबरा रहे हैं? उनकी किताब को प्रकाशित होने से कौन रोक रहा है। खरगे ने दावा किया कि पूरा देश जानता है कि भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा है। वो देशभक्ति की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं पर 2020 में गलवान में हमारे 20 जवानों के सर्वोच्च बलिदान के बाद मोदी जी खुद चीन को क्लीन चिट थमा देते हैं। क्या ये सच नहीं है? उन्होंने कहा कि क्या संसद में इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर देश को विश्वास में नहीं लिया गया है? लोकतंत्र की जननी की बात करने वाले लोकतंत्र की आत्मा को रौंदने में क्यों जुटे हुए हैं।

पिता के सामने ही कार समेत गड्ढे में समा गया इंजीनियर, चिल्ला कर मांगता रहा हेल्प

तीन दिन बाद पानी से निकाली गई युवराज की कार



सतपाल सिंह तंवर
दिल्ली ब्यूरो प्रमुख



नोएडा। शुक्रवार 16 जनवरी की रात को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 के पास हुए दर्दनाक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार समेत डूबने से मौत हो गई थी। जिस कार में मृतक युवराज मेहता थे उसे एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के करीब तीन दिन बाद पानी से बाहर निकाल लिया। बीते शुक्रवार रात को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 के पास हुए दर्दनाक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार समेत डूबने से मौत हो गई थी। जिस कार में मृतक युवराज मेहता थे उसे एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के करीब तीन दिन बाद पानी से बाहर निकाल लिया। कई घंटे तक पानी के अंदर पड़ी रही कार की हालत बहुत खराब थी। इसके शीशे टूटे हुए थे और सनरूफ भी टूट गया था। माना जा रहा है कि पानी के अत्यधिक दबाव के कारण गाड़ी के शीशे टूटे होंगे। कार बरामद होने के बाद अब साफ हो सकेगा कि कहीं कार



में कोई खराबी के कारण तो यह हादसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी कार की फॉरेंसिक जांच कराई जाने की तैयारी की जा रही है।

हादसे के बाद जागा प्रशासन

हादसे के बाद राज्य सरकार ने नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम को हटा दिया। इस घटना की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार से अपना काम शुरू कर दिया है और

नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर जांच की। करीब 2 घंटे नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में रहने के बाद, एसआईटी घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसआईटी से पांच दिन में जांच रिपोर्ट तलब की गई है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने एमजेड विजटाउन के मालिक बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-150 क्षेत्र में भारी जलभराव के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार पानी से भरे गड्ढे अंडरपास में फंस गई थी, जिससे कार समेत व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, विकास प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। ग्रेटर नोएडा सेक्टर-150 में सड़क हादसे के बाद दलदल में डूबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि युवराज की मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार उनके फेफड़ों में करीब साढ़े तीन लीटर पानी भरा हुआ पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि वह काफी देर तक पानी में डूबे रहे। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कहा गया है



कि लंबे समय तक पानी में रहने से उनके फेफड़ों में भारी मात्रा में पानी चला गया, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई और दम घुटने की स्थिति पैदा हुई। इसी दौरान शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ने से हार्ट फेलियर भी हुआ, जो मौत का तत्काल कारण बना।

मेरठ जोन एडीजी भानु भास्कर ने कहा, हमारी एसआईटी ने इसमें काम शुरू कर दिया है, शासन के निर्देश पर पांच दिन में इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद ये देखना होगा कि ये किन कारणों से और परिस्थितियों में यह घटना घटी है। हम घटना की जांच कर रहे हैं जांच के बाद हम प्रशासन को अवगत कराएंगे सेक्टर 150 के निवासियों का कहना है कि खतरे को लेकर पहले से ही सभी को पता था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले उसी जगह पर ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि यह कोई अनजानी गलती नहीं बल्कि लापरवाही का एक पैटर्न था।

27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की SUV कार शनिवार को नोएडा के सेक्टर 150 में ITS ले ग्रैंडियोस के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिस कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुखद घटना थी जिसे टाला जा सकता था।

इंजीनियर की मौत के बाद एक्शन



इस घटना पर कार्रवाई करते हुए, अथॉरिटी ने एक जूनियर इंजीनियर की सेवाएं खत्म कर दी हैं और इलाके में ट्रैफिक से जुड़े कामों के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। रविवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान में, अथॉरिटी ने कहा कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकेश एम, ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है और नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को तुरंत नौकरी से निकालने का निर्देश दिया था। सेक्टर 150 और उसके आस-पास ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ब् ने डेवलपर लोटस के अलॉटमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में संबंधित विभागों से विस्

तृत रिपोर्ट मांगी और साइट पर सुरक्षा इंतजामों की पूरी समीक्षा का आदेश दिया।

मॉल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया गड्ढा

यह हादसा रात करीब 12:30 बजे हुआ, जब सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी का रहने वाला युवराज काम से घर लौट रहा था। घने कोहरे और कम रोशनी में अपनी ग्रैंड विटारा चलाते हुए, वह जै ले ग्रैंडियोस के पास एक मोड़ से गुजर रहा था, तभी SUV एक टूटी हुई बाउंड्री वॉल से टकराकर एक निर्माणाधीन कमर्शियल प्रोजेक्ट के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। निवासियों का कहना है कि यह गड्ढा करीब दो साल पहले एक मॉल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था और उसे खुला छोड़ दिया गया था। समय के साथ, पास की सोसाइटियों से निकलने वाला सीवेज वहां जमा हो गया क्योंकि हिंडन नदी में पानी छोड़ने पर रोक थी, जिससे यह एक गहरा, रुका हुआ पानी का तालाब बन गया। एफआईआर में बताया गया कि प्लॉट के चारों ओर कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर नहीं था। FIR में कहा गया है, बिल्डरों की तरफ से गंभीर लापरवाही थी। ए बता दें कि युवराज को तैरना नहीं आता था, वह इसलिए डूबती हुई गाड़ी से बाहर निकला और उसकी छत पर चढ़ गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच वह अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला।



कर मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसने अपने पिता, राज कुमार मेहता को भी फोन किया और अपनी WhatsApp लोकेशन शेयर की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डायरेक्टर राज मेहता कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचे और 112 डायल किया। लेकिन विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि गड्ढे के किनारे खड़े लोग भी युवराज को ढूँढ नहीं पा रहे थे, हालांकि उन्हें उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। बचाव अभियान में शामिल एक सीनियर अधिकारी ने इस ऑपरेशन को लगभग अंधेरे में किया गया काम बताया। उन्होंने कहा, 'शहमें सिर्फ रोशनी की एक पतली किरण दिख रही थी, शायद उसके फोन से।' एक और अधिकारी ने बताया कि घने कोहरे की वजह से टीमें '10 मीटर दूर भी नहीं देख पा रही थीं।'

विरोध प्रदर्शन, एफआईआर और लगाए गए बैरिकेड

घटना के बाद, निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने अपर्याप्त बैरिकेडिंग, रिप्लेक्टर की कमी और अधिकारियों को बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। परिवार की शिकायत के आधार पर दो रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि पुलिस ने बचाव अभियान में लापरवाही से इनकार किया है। एफआईआर में राज मेहता ने आरोप लगाया कि निवासियों ने नोएडा अथॉरिटी से नाले के पास बैरिकेड और रिप्लेक्टर लगाने के लिए बार-बार अनुरोध किया था, लेकिन बार-बार दुर्घटनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। विरोध प्रदर्शनों के बाद, नोएडा अथॉरिटी ने आखिरकार उस जगह पर बैरिकेड लगा दिए। लोटस ग्रीन्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह प्लॉट 2019-20 में नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी से गृहप्रवेश ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया था।

युवराज मेहता गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और हाइब्रिड वर्क शेड्यूल फॉलो करते थे, ज्यादातर घर से काम करते थे और हफ्ते में दो बार ऑफिस जाते थे। शक्रवार को वह



ऑफिस गए थे और देर रात घने कोहरे के बीच घर लौट रहे थे। वह अपने पिता के साथ टाटा यूरेका पार्क में रहते थे। उनकी मां का दो साल पहले निधन हो गया था। युवराज परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी बड़ी बहन शादीशुदा है और UK में रहती है।

योगी सरकार के दो बड़े एक्शन, नोएडा सीईओ हटाए गए, जांच के लिए एसआईटी भी गठित

नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने नोएडा के सीईओ डॉ. लोकेश एम को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT गठित हुई। मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित हुई SIT में एडीजी जोन मेरठ व चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल हैं। एसआईटी जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी।

एनडीआरएफ ने सुबह बरामद किया था इंजीनियर का शव

इस हादसे के बारे में नॉलेज पार्क थ.ने के अनुसार, सेक्टर 150 के पास निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में कार गिरने की सूचना देर रात करीब सवा 12 बजे मिली। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान शुरू किया गया और दमकल विभाग, राज्य



आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और स्थानीय पुलिस की टीमों की मदद से शनिवार सुबह शव बरामद किया गया।

इंजीनियर युवराज की मौत मामले में उठ रहे कई सवाल

आखिर बेसमेंट में पानी क्यों भरा हुआ था? हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में इतनी बारिश भी नहीं हुई कि किसी गड्ढे में इतना पानी भरा हो कि कार उसमें डूब जाए। दूसरा सवाल ये कि आखिर ये किस तरह की रेस्क्यू टीम थी, जो बीच शहर में एक शख्स को बेसमेंट में डूबने से बचा नहीं सकी। ऐसी स्थिति में किसी प्राकृतिक आपदा का सामना हम कैसे करेंगे? युवराज के पिता ने बयान दिया जो रेस्क्यू टीम आई उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। एक डिलिवरी बॉय ने रस्सी फेंककर युवराज को बचाने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा, यही से दूसरा सवाल उठता है। जब सूचना डूबने की मिली थी तो कोई तैराक मौके पर क्यों नहीं गया? क्या रेस्क्यू टीम को चलाने वाले लोगों की भी जवाबदेही तय होगी? सबसे अहम सवाल यह कि इंजीनियर के डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बचाने के लिए करीब 2 घंटे का समय था। लेकिन इस दो घंटे में भी इंजीनियर को बाहर नहीं निकाला जा सका।

लव मैरिज करने वालों का गांव से होगा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार



मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पंचेवा गांव का फैसला

मध्य प्रदेश के एक गांव में नए फरमान ने सभी को चकित कर दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पंचेवा गांव में ऐलान किया गया है कि लव मैरिज करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये बयान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पंचेवा गांव में ऐलान कर रहे अरुण सांखला का था। इस दौरान गांव के सरपंच और पंच भी मौजूद थे और वे इस ऐलान से सहमत भी थे। लगभग चार हजार लोगों की आबादी वाले पंचेवा गांव में पिछले कुछ महीनों में कई युवा जोड़ों ने प्रेम विवाह किया और इनमें से ज्यादातर अंतरज.तीय शादियां थीं। गांव में इन शादियों को लेकर कई सवाल थे। 22 जनवरी को गांव के अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर जनसभा करने की बात वायरल होने लगी और 23 तारीख की शाम गांव के अंदर बने राम मंदिर के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए। जिला कलेक्टर मीशा सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करने

और पीड़ित पक्ष की मदद करने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला?

पंचेवा गांव में लोग अलग-अलग समूहों में इस ऐलान पर चर्चा करते नजर आए। इस बारे में जिन लोगों से बात हुई उनमें से ज्यादातर ग्रामीणों का कहना था, 23 तारीख को सुनाया गया फैसला बिल्कुल सही है। घर से लड़का-लड़की भागकर शादी करेंगे तो मां-बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। गांव में पिछले एक साल में 6-7 प्रेम विवाह हुए हैं। 18 जनवरी को गांव में एक अंतरजातीय जोड़े ने प्रेम विवाह के लिए घर छोड़ दिया। इसके पांच दिन बाद 23 तारीख को ग्रामीणों ने सभा की और प्रेम विवाह पर रोक लगाने और प्रेम विवाह करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने के लिए मीटिंग रखी। गांव में छोटे-बड़े लगभग 7-8 मंदिर हैं, जहां 23 तारीख को प्रेम विवाह रोकने की मीटिंग की घोषणा करवाई गई। इसी मीटिंग के बाद अरुण सांखला ने सबकी

सहमति से लिए गए फैसले को सुनाते हुए प्रेम विवाह करने वालों के बहिष्कार का फरमान सुना दिया। इस बहिष्कार के तहत गांव में संबंधित लोगों को दूध, चाय और राशन जैसी जरूरी चीजे न देने की बात कही गई। मंदिर में प्रवेश पर रोक का भी ऐलान हुआ।

इस फरमान की जद में आए दीनदयाल जाट और मनीषा पाटीदार

इस फरमान की जद में आए आठ महीने पहले शादी करने वाले दीनदयाल जाट और मनीषा पाटीदार। दोनों बालिग हैं और पिछले छह साल से एक-दूसरे को जानते हैं। दीनदयाल कहते हैं कि हम लोग छह साल पहले गांव के एक मेले में मिले थे। फिर धीरे-धीरे फोन पर बात होने लगी। जब हम लोग शादी की उम्र में पहुंचे तो हमने भागकर कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और लगभग 25 किलोम.

ीटर दूर नामली में रहने लगे। दीनदयाल बताते हैं कि मैंने सुबह फेसबुक पर एक वीडियो वायरल होते देखा।

उसमें मेरा और मेरे चाचा का भी नाम था और हमारा बहिष्कार करने का भी आदेश था। मैंने अपने चाचा को फोन किया तो उन्होंने सारी कहानी बताई। वह कहते हैं कि मैं तो तब से ही यह सोच रहा हूँ कि जिस शादी को कोर्ट ने वैध माना, जिस पर पुलिस की सहमति रही। जिसमें हम दोनों खुश हैं और जिस शादी का अधिकार हमें संविधान ने दिया, उसका बहिष्कार करने का हक गांव वालों को किसने दिया।

प्रशासन ने क्या बताया?

रतलाम की जिला कलेक्टर मीशा सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार दा. नों ने ही इस घटना को निंदनीय और नागरिक स्वतंत्रता के हनन का मामला बताया। जिला कलेक्टर मीशा सिंह ने बताया कि फिलहाल अरुण सांखला और पांच अन्य ग्रामीणों से 25 हजार का बॉन्ड इस शर्त के साथ भरवाया गया है कि अगर अगले छह महीने में इनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार कहते हैं कि कुछ कपल्स ने शादी की थी जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एक जनसभा की और सामाजिक बहिष्कार की बात कही, जिसका वीडियो हमारे पास आया था। हमने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। देखिए यह सिविल लिबर्टी (नागरिक स्वतंत्रता) का मामला है इसलिए हमने इलाके में पुलिस पैट्रोलिंग भी बढ़ा दी है ताकि नागरिकों के बीच विश्वास बनाया जा सके। हालांकि दीनदयाल और उनके परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी अब तक कोई मदद नहीं की है।

प्रेम विवाह का समर्थन करने वाले भी परेशान

इस बहिष्कार की मार सिर्फ दीनदयाल और मनीषा तक सीमित नहीं रही। दीनदयाल के चाचा निर्मल जाट ने इस शादी का समर्थन किया था। इसके बाद उन्हें भी गांव से अलग-थलग कर दिया गया। निर्मल जाट कहते हैं कि श्रीमान मैं तो फरमान जारी होने के बाद से गांव नहीं गया हूँ। मुझे डर है कि अगर

लौटा तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है। गांव वालों ने यह भी कहा कि जो कोई परिवार की मदद करेगा उसके साथ भी हिंसा होगी। दीनदयाल बताते हैं कि 24 जनवरी से उनका परिवार गांव से बाहर ही रह रहा है। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि डर सिर्फ बहिष्कार का नहीं बल्कि हिंसा का भी था।

गांव के सरपंच ने क्या कहा?

गांव के सरपंच योगेश मीणा का कहना है कि पिछले एक साल में पंचेवा में छह से सात प्रेम विवाह हुए हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर मामलों में लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी की। सरपंच का दावा है कि इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था और इसी वजह से लोगों ने बैठकर फैसला लिया। उनका कहना है कि देखिए यह फैसला किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि गांव की सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया। यहां कई मामले हुए जब लड़के और लड़कियों ने भाग कर शादी कर ली। वायरल वीडियो में दिखने वाले पंच अरुण सांखला कहते हैं कि यह कदम बच्चों को माता-पिता की अनुमति के बिना शादी करने से रोकने के लिए था ताकि परिवारों को दुख न हो। बच्चे ऐसी शादियां करते हैं और फिर वापस आकर उसी गांव में अपने मां-बाप के सामने रहते हैं, ऐसे में परिजनों को कितना दुख होता है। इसको रोकने के लिए ऐसा फैसला सुनाया गया था। हालांकि, अब प्रशासनिक दखल के बाद अरुण सांखला का कहना है कि हमारे यहां सभी अधिकारी और प्रशासनिक लोग आए थे जिनसे बातचीत में हमने कहा कि गांव में कोई नियम लागू नहीं किया जा रहा और न ही हम किसी का बहिष्कार करेंगे।

अंतरजातीय शादी है असल मुद्दा

दीनदयाल पंचायत की इन दलीलों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि असल वजह उनकी अंतरजातीय शादी है। वह जाट समाज से हैं जबकि मनीषा पाटीदार समाज से आती हैं। दीनदयाल कहते हैं कि गांव की बैठक में यही सवाल उठाया गया कि जाट समाज के लड़के ने पाटीदार समाज की लड़की से

शादी कैसे कर ली। दीनदयाल ने कहा, हम दोनों अलग जातियों से हैं इसलिए इतना बहिष्कार हो रहा है। अगर एक ही जाति में होते तो ऐसा नहीं होता। वहीं, मनीषा ने दीनदयाल की ओर देखते हुए कहा कि प्रेम विवाह में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि इस विवाद के चलते शादी के बाद की जिंदगी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन हो गई। दीनदयाल का कहना है कि मुझे यह अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद न सरकार मेरे साथ खड़ी होगी और न ही पुलिस। मुझे लगा था कि कानून से हमें सुरक्षा मिलेगी लेकिन बहिष्कार और धमकियों के बीच अभी तो असहाय ही हैं, कानून की कोई मदद नहीं मिली है। जो लोग परिवार के साथ खड़े हुए उनके लिए भी हालात आसान नहीं हैं। निर्मल जाट कहते हैं कि बहिष्कार सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। मजदूरी और रोजगार पर भी असर पड़ा है। हालांकि जब हमने परिवार के सुरक्षा न मिलने के आरोपों पर पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है और एक टीम हालात का जायजा ले रही है। ग्रामीण अपना फैसला वापस लेने के बारे में कह रहे हैं जबकि दीनदयाल और उनके परिवार को इस बात का भरोसा नहीं है कि बहिष्कार का फैसला और धमकियां पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। दीनदयाल कहते हैं कि वह अपने गांव लौटना चाहते हैं। उनके चाचा निर्मल जाट भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो पहले थी। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल है कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे कोई भी प्रेम विवाह करने की हिम्मत कैसे करेगा। ऐसे में तो दो लोग जो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं वो बिछड़ जाएंगे और शायद ऐसे में जीना भी पसंद न करें। वह कहते हैं कि ये डर सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन जैसे तमाम लोगों का है जो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के पार्टनर के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं और जिन्हें अब यह डर सता रहा है कि उस फैसले की कीमत पूरा परिवार चुकाएगा।

कटसी बीबीसी हिंदी डॉट काम

भारत की नियति नेतृत्व करना है, संतुलन बनाना नहीं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों उच्चतम मंच पर अपनी जगह का दावा करे?



विकास पारिक (लंदन) विदेश प्रतिनिधि



पचहत्तर वर्षों तक, भारत का विदेश नीति प्रतिष्ठान एक विचित्र भ्रम में जीता रहा: कि संयम में ही सद्गुण है, कि महानता किनारे खड़े रहकर हासिल की जा सकती है, और कि नैतिक अधिकार का सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी का पक्ष लेने से इनकार करके किया जाता है। नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, जो कभी शीत युद्ध की बारूदी सुरंगों से गुजरते हुए एक नवस्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक चतुर जीवन रक्षा रणनीति थी, जमकर एक कट्टर सिद्धांत बन गया — सैद्धांतिक तटस्थता के वेश में रणनीतिक कारगरता का एक सुविधाजनक बहाना। वह युग समाप्त हो चुका है। या कम से कम, होना चाहिए।

आज भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जो शायद किसी सभ्यता के जीवनकाल में एक ही बार आता है। 1.4 अरब लोगों, विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक युद्ध-परीक्षित सेना, एक बढ़ते तकनीकी आधार, और सिलिकॉन वैली से लेकर वेस्टमिंस्टर तक प्रभाव रखने वाले प्रवासी समुदाय के साथ, सवाल अब यह नहीं है कि भारत के पास नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या उसके पास इच्छाशक्ति है। और इसका उत्तर, उत्तरोत्तर, हाँ है कृ जो ल्यूटियंस दिल्ली के पुराने प्रहरियों द्वारा नहीं, बल्कि एक नई राजनीति

तिक चेतना द्वारा संचालित है जो शक्ति को शर्मिंदगी की वस्तु नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की वस्तु मानती है।

2023 में G20 की अध्यक्षता केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं था। यह एक इरादे की घोषणा थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” के बैनर तले नई दिल्ली में विश्व नेताओं की मेजबानी की, तो प्रतीकवाद अचूक था। भारत अब वैश्विक व्यवस्था में एक प्रतिभागी बने रहने से संतुष्ट नहीं था। वह इसे आकार देने का इरादा रखता था। अफ्रीकी संघ को 2020 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना — जिसका भारत ने समर्थन दिया — एक कूटनीतिक उत्कृष्ट चाल थी जिसने विकासशील विश्व को संकेत दिया कि नई दिल्ली उनकी आकांक्षाओं को समझती है क्योंकि वह उन्हें साझा करती है। यह पश्चिमी शैली की कृपालु उदारता नहीं थी। यह एक उभरती शक्ति का वैश्विक दक्षिण से कहना थारु हम आपमें से एक हैं, और हम आपकी आवाज उन कमरों तक ले जाएँगे जहाँ निर्णय लिए जाते हैं।

भारत की वैश्विक भूमिका के लिए दक्षिणपंथी दृष्टिकोण कांग्रेस-युग के प्रतिमान से मौलिक रूप से भिन्न है। यह गुटनिरपेक्षता की झूठी विनम्रता को, पश्चिमी संस्थानों के प्रति प्रतिवर्ती श्रद्धा को, और इस धारणा को अस्वीकार करता है कि भारत को हमेशा किसी और की व्यवस्था में एक जिम्मेदार हितधारक बने रहना चाहिए। इसके बजाय, यह दावा करता है कि भारत को एक अग्रणी शक्ति होना चाहिए कृ एक सभ्यतागत

राज्य जिसमें एजेंडा तय करने, अपनी शर्तों पर गठबंधन बनाने, और जब उसके हित माँगें तो ‘नहीं’ कहने का आत्मविश्वास हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर विचार करें, जो संस्थाओं में सबसे पुरातन है। स्थायी पाँच — संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन — 1945 की शक्ति वास्तविकताओं को दर्शाते हैं, 2025 की नहीं। भारत, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस मेज से बाहर रखा गया है जहाँ युद्ध, शांति और प्रतिबंधों के बारे में बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं। इस व्यवस्था की विसंगति स्वतः स्पष्ट है। फ्रांस और ब्रिटेन, जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ भारत से छोटी हैं और जनसंख्या उसका एक अंश है, अस्सी वर्ष पहले एक युद्ध जीतने के आधार पर वीटो रखते हैं। भारत किसी भी P5 सदस्य से अधिक सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देता है। यह विकासशील विश्व की फार्मसी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की IT रीढ़ है, और ग्रह पर सबसे पेशेवर सेनाओं में से एक वाला परमाणु-सशस्त्र राज्य है। किस तर्क से यह कमरे से बाहर रहता है? दक्षिणपंथी तर्क केवल यह नहीं है कि भारत प्रतिष्ठा के कारणों से एक सीट का हकदार है — हालाँकि प्रतिष्ठा उदारवादियों की परवाह से कहीं अधिक मायने रखती है। यह है कि वैश्विक शासन की वर्तमान संरचना टूट चुकी है, और भारत का शामिल होना इसे ठीक करने की एक आवश्यक शर्त है। भारत के बिना एक सुरक्षा परिषद विश्वसनीय रूप से यह दावा नहीं कर सकती कि वह

विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोपीय राजधानियों में डिजाइन किया गया जलवायु शासन उन अरब लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित नहीं कर सकता जो अभी भी गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। एक वैश्विक स्वास्थ्य ढाँचा जो भारतीय दवा क्षमता को दरकिनार करता है कृ जैसा कि पश्चिम ने COVID-19 टीका वितरण के शुरुआती चरणों में करने का प्रयास किया, इससे पहले कि उसे रेंगते हुए वापस आना पड़ा कृ न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अक्षम भी है।

यह हमें रणनीतिक स्वायत्तता के प्रश्न पर ले आता है, एक वाक्यांश जो भारत की वर्तमान विदेश नीति सोच का मार्गदर्शक सितारा बन गया है। पुरानी गुटनिरपेक्षता निष्क्रिय थीय रणनीतिक स्वायत्तता सक्रिय है। इसका अर्थ है कि भारत प्रत्येक प्रमुख शक्ति गुट के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करते हुए किसी एक खेमे में खींचे जाने से इनकार करता है। भारत-रूस संबंध इस दृष्टिकोण का सबसे अधिक गलत समझा गया उदाहरण है। पश्चिमी टिप्पणिकाओं ने, विशेष रूप से यूक्रेन आक्रमण के बाद, मॉस्को की निंदा करने से भारत के इनकार पर हैरानी और निराशा व्यक्त की है। दक्षिणपंथी भारतीय दृष्टिकोण से, यह हैरानी अपने आप में हैरान करने वाली है। रूस पाँच दशकों से अधिक समय से भारत का सबसे विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है। रूसी प्लेटफॉर्म भारत के सैन्य हार्डवेयर की रीढ़ हैं। रूसी ऊर्जा कृ 2022 से भारी छूट पर खरीदा गया तेल कृ एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा रही है जो अपने कच्चे तेल का अस्सी प्रतिशत से अधिक आयात करती है। जब 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन था, तब रूस अडिग खड़ा रहा। जब शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को दाँतों तक हथियारबंद कर रहा था, तब सोवियत संघ ने नई दिल्ली के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत से यह अपेक्षा करना कि वह इस संबंध को इसलिए त्याग दे क्या कि वाशिंगटन को यह असुविधाजनक लगता है, यह मौलिक रूप से गलत समझना है कि राष्ट्र अपने हितों की गणना कैसे करते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का संधि सहयोगी नहीं है। वह नाटो का सदस्य नहीं है। वह अपनी स्वयं की खतरे की धारणाओं वाला एक संप्रभु राज्य है, और वे खतरे की धारणाएँ रूस से नहीं बल्कि चीन से प्रभावित

हैं कृ एक भेद जिसे कई पश्चिमी विश्लेषक लगातार समझने में विफल रहते हैं। और फिर भी, भारत-अमेरिका साझेदारी का गहरा होना इस दृष्टिकोण के लिए समान रूप से केंद्रीय है। दक्षिणपंथी स्थिति अमेरिका-विरोधी नहीं है; यह भारत-समर्थक है। BECA, LEMOA और COMCAS। जैसे रक्षा समझौतों ने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को रूपांतरित कर दिया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल (iCET) सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष में सहयोग की नींव रख रही है। भारत में अमेरिकी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय — चालीस लाख से अधिक — इजरायली के बाद वाशिंगटन में सबसे शक्तिशाली प्रवासी लॉबी है। रणनीतिक तर्क सीधा हैरु संयुक्त राज्य अमेरिका को हिंद-प्रशांत में चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में भारत की आवश्यकता है, और भारत को अपने उत्थान को तेज करने के लिए अमेरिकी तकनीक, निवेश और कूटनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। यह भावना का गठबंधन नहीं हैय यह हितों का तालमेल है। और ठीक इसीलिए क्योंकि यह विचारधारा-आधारित नहीं बल्कि हित-आधारित है, यह रूस के साथ भारत के संबंध के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है कृ उन लोगों की असुविधा के बावजूद जो विश्व को द्विआधारी (बाइनरी) दृष्टि से देखते हैं। ऊर्जा सुरक्षा वह सूत्र है जो इन संबंधों को एक साथ जोड़ता है। भारत अपनी वृद्धि को पश्चिमी नैतिक उपदेशों से संचालित नहीं कर सकता। उसे तेल, गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, और वह इन्हें उससे प्राप्त करेगा जो सबसे अच्छी शर्तें प्रदान करे। बाजार मूल्य से चालीस डॉलर कम पर रूसी कच्चा तेल भू-राजनीतिक विश्वासघात नहीं है; यह विवेकपूर्ण आर्थिक नीति है। साथ ही, भारत सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है — इसलिए नहीं कि पेरिस समझौता इसकी माँग करता है, बल्कि इसलिए कि ऊर्जा स्वतंत्रता एक ऐसे देश के लिए रणनीतिक अनिवार्यता है जो खाड़ी देशों या मॉस्को या किसी और के बंधक बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस रणनीति का वैश्विक दक्षिण आयाम परोपकार नहीं है। यह एक समर्थन आधार का निर्माण है। जब भारत अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए ऋण राहत, विकासशील देशों के लिए टीका समानता, या प्ले और विश्व बैंक में सुधारित ऋण प्रथाओं का समर्थन

करता है, तो वह उन राज्यों का गठबंधन बना रहा है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे, बहुपक्षीय वार्ताओं में भारत का साथ देंगे, और नेतृत्व के लिए बीजिंग के बजाय नई दिल्ली की ओर देखेंगे। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, अपने ऋण जालों और सामरिक बंदरगाह अधिग्रहणों के साथ, एशिया और अफ्रीका भर में भारी आक्रोश पैदा कर चुकी है। भारत का प्रति-प्रस्ताव पारदर्शी, सम्मानजनक, और उपनिवेशवाद तथा अल्पविकास के साझा अनुभव में निहित — उत्तरोत्तर आकर्षक होता जा रहा है।

यही वह दृष्टिकोण हैरु एक भारत जो कार्य करने की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करता, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए क्षमा नहीं माँगता, और अपने सम्यतागत हितों को एक क्षीण होती पश्चिमी-नेतृत्व वाली व्यवस्था की प्राथमिकताओं के अधीन नहीं रखता। यह एक ऐसा भारत है जो रूस के साथ व्यापार करता है, अमेरिका के साथ साझेदारी करता है, चीन से प्रतिस्पर्धा करता है, और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करता है कृ सब एक साथ, सब बिना किसी विरोधाभास के।

आलोचक इसे अहंकार कहेंगे। वे अति-विरुद्ध तार की, महान शक्तियों को उकसाने की, क्षमता से अधिक लेने की चेतावनी देंगे। ये वही आलोचक हैं जिन्होंने कहा था कि भारत प्रतिबंधों के तहत ढहे बिना परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, जिन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक असंभव हैं, जिन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का निरसन कश्मीर को आग में झोंक देगा।

वे तब गलत थे। वे अब भी गलत हैं। भारत का समय आ गया है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र इसे उस दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ेगा जिसकी यह माँग करता है कृ या एक बार फिर किनारे खड़े रहने की सुविधाजनक साधारणता में लौट जाएगा, अन्य राष्ट्रों की तालियाँ बजाते हुए जब वे विश्व को आकार देते हैं। उनके लिए जो भारत की सम्यतागत नियति में विश्वास करते हैं, उत्तर स्पष्ट है। भारत कभी संतुलन बनाने के लिए नहीं बना था। भारत नेतृत्व करने के लिए बना था।

इस लेख में व्यक्त विचार भारत की भू-राजनीतिक स्थिति पर एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और आवश्यक रूप से इस प्रकाशन के संपादकीय रुख को प्रतिबिंबित नहीं करते।

POWERING INDIA'S GROWTH, FUELING THE NATION'S FUTURE



BCCL STRENGTHENING THE NATION WITH
RESPONSIBLE ENERGY



Bharat Coking Coal Limited

(A Mini Ratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

ऊर्जा से प्रगति, विकास से विश्वास

- ① सतत खनन, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व
- ① देश की औद्योगिक एवं ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, भारत के कोकिंग कोल उत्पादन में अग्रणी भूमिका
- ① उन्नत तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक खनन
- ① कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, नागरिक सुविधाओं का विस्तार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
- ① झरिया मास्टर प्लान के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, कल्याण और आजीविका में सहयोग हेतु सतत प्रयास



भारत अमेरिका के साथ कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी का व्यापार बढ़ाएगा : पुरी



गोवा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी सहित संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को गहरा करने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। पुरी ने कहा कि भारत वर्तमान में अमेरिका से लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की ऊर्जा आयात करता है, और हाल ही में उसने अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भी बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिका में निर्माणाधीन या अंतिम निवेश निर्णय के करीब पहुंच चुके एलएनजी द्रवीकरण परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की इक्विटी भागीदारी शामिल है। ये टिप्पणियां इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 के दौरान की गईं, जहां मंत्रालय ने नई दिल्ली में आईईडब्ल्यू 2025 के दौरान हुई चर्चाओं के अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी के भविष्य पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। पुरी ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच सहयोग सरकार द्वारा भारत को एक विश्वसनीय दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदार के रूप में स्थापित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक ऊर्जा सीईओ के साथ हुई नौवीं गोलमेज बैठक का हवाला दिया, जिसमें कंपनी के नेताओं ने भारत की विकास गति पर भरोसा जताया और निवेश बढ़ाने में रुचि दिखाई। पुरी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में 500 अरब अमेरिकी डॉलर का अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें अकेले अन्वेषण और उत्पादन में अनुमानित 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावना शामिल है। वैश्विक सीईओ ने भारतीय तेल विपणन कंपनियों के साथ गहन सहयोग और अपस्ट्रीम अवसरों के विस्तार में भागीदारी की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों के आधार में विविधता ला रहा है, लगभग 40 देशों से कच्चा तेल और 18 स्रोतों से एलएनजी आयात कर रहा है, जबकि 150 से अधिक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है। पुरी ने कहा कि अमेरिका के अलावा, भारत ऊर्जा आयात बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए कनाडा जैसे संसाधन संपन्न देशों से संपर्क कर रहा है। जापान और आइसलैंड के साथ अलग-अलग गोलमेज बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें हाइड्रोकार्बन, इथेनॉल और जैव ईंधन, एलएनजी मूल्य श्रृंखला, भूतापीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले से ही पायलट सीसीएस परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा अन्वेषण के अवसरों की जांच की जा रही है। पुरी ने कहा कि आईईडब्ल्यू के दौरान एलएनजी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और कम कार्बन वाले ईंधनों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एलएनजी और गैस बाजारों में सहयोग के लिए इंडियन ऑयल और म्छम् के बीच समझौता और डीजल वाहनों को एलएनजी में परिवर्तित करने के लिए बीपीसीएल की लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के समझौते भारत की दोहरी रणनीति को दर्शाते हैं, जिसके तहत हाइड्रोकार्बन सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन और नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

Indian Oil Q3 Results 2026: 322% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू 2.31 लाख करोड़ हुआ



सरकार की एक प्रमुख महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) ने दिसंबर तिमाही 2025 का फाइनंशियल रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में उसका टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में चार गुना की भारी बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी मजबूत रिफाइनरी मार्जिन और बेहतरीन परिसंचालन प्रदर्शन की वजह से आई है। इंडियन ऑयल ने इस तिमाही 12,126 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 2874 करोड़ रुपये था। यानी इसमें 322 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

रेवेन्यू में 7% का उछाल

इस दौरान IOC ने ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 7% की बढ़त हासिल की है। दिसंबर तिमाही के लिए यह 2.31 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल की दिसंबर तिमाही में 2.16 लाख करोड़ रुपये था। कंपनी ने पिछले साल के कमजोर बेस के बाद इस तिमाही मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। पिछले साल कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, इन्वेंट्री लॉस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी से मार्जिन पर दबाव रहा। वहीं, दिसंबर 2025 तिमाही में क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता, बेहतर रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स और प्रमुख एसेट्स में बेहतर उत्पादन क्षमता से फायदा हुआ है।

पेट्रोलियम सेगमेंट से आया सबसे ज्यादा रेवेन्यू

रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए IOC के रेवेन्यू में इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दबदबा बना रहा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेगमेंट से रेवेन्यू 2.17 लाख करोड़ रुपये आया है, जो कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट ने 6,936 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि गैस सेगमेंट ने कमाई में 11,691 करोड़ रुपये का योगदान दिया। कंपनी के खर्च में भी बढ़ोतरी अगर दिसंबर 2025 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) के कुल खर्च की बात करें, तो यह 2.16 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की तीसरी तिमाही में यह 2.15 लाख करोड़ रुपये था। यानी कंपनी पर कच्चे तेल और ऑपरेशनल कॉस्ट का दबाव बना हुआ है। प्रस्तुति-ग्राइम स्पेक्टोर डेस्क.

एलआईसी ने तिमाही में नेट प्रॉफिट में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की



लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) ने तिमाही वित्त वर्ष 26 के लिए 12,930 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो तिमाही वित्त वर्ष 25 में रिपोर्ट किए गए 11,008.65 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से 17 प्रतिशत ज्यादा है। इस बीच, इंश्योरेंस कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम थ्रू 26 की तीसरी तिमाही के दौरान बढ़कर 1,25,988.15 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के बयान के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 33,998 करोड़ रुपये था, जबकि 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए यह 29,138 करोड़ रुपये था, जो 16.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम (थ्रू) (प्लू ए के अनुसार) के हिसाब से मार्केट शेयर के मामले में, स्ब भारतीय जीवन बीमा व्यवसाय में मार्केट लीडर बना हुआ है,

जिसका 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए कुल मार्केट शेयर 57.07 प्रतिशत है, जबकि 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए यह 57.42 प्रतिशत था। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए, स्ब का इंडिविजुअल बिजनेस में मार्केट शेयर 35.84 प्रतिशत और ग्रुप बिजनेस में 71.36 प्रतिशत था। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के लिए कुल प्रीमियम इनकम 3,71,293 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 3,40,563 करोड़ रुपये थी, जो 9.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के लिए इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम इनकम 44,941 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 42,441 करोड़ रुपये थी, जो 5.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के लिए इंडिविजुअल रिन्यूअल प्रीमियम इनकम 1,91,050 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,78,975 करोड़ रुपये थी, जिसमें 6.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के लिए कुल इंडिविजुअल बिजनेस प्रीमियम पिछले साल की इसी अवधि के 2,21,416 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,35,991 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 6.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के लिए ग्रुप बिजनेस का कुल प्रीमियम इनकम 1,35,302 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,19,147 करोड़ रुपये था, जिसमें 13.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। प्रस्तुति-ग्राइम स्पेक्टोर डेस्क.

एसजेवीएन ने विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया



शिमला। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भ. पेंद्र गुप्ता ने बताया कि एसजेवीएन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत स्टेशन ने दिनांक 5 फरवरी, 2026 को एक वित्तीय वर्ष में 2000 मिलियन यूनिट का अब तक का सबसे तेज (शीघ्रतम) विद्युत उत्पादन दर्ज किया है। यह उपलब्धि दिनांक 14 फरवरी, 2020 को बनाए गए गत रिकॉर्ड से नौ दिन पूर्व हासिल की गई, जो विद्युत स्टेशन के गत ग्यारह वर्षों के प्रचालन में विद्युत उत्पादन का उत्कृष्ट निष्पादन है। इस अवसर पर एसजेवीएन प्रबंधन ने कर्मचारियों और इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश

सरकार, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और शिमला एवं कुल्लू के जिला प्रशासन के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता ने परियोजना प्रमुख, विकास मारवाह के नेतृत्व में रामपुर जलविद्युत स्टेशन की टीम के अनुशासन और सुदृढ़ कार्यशैली की सराहना की। अजय कुमार शर्मा, निदेशक(कार्मिक) ने इस उपलब्धि का श्रेय सामूहिक योग्यता, प्रभावी मानव संसाधन प्रथाओं और समेकित आंतर-विभागीय सामंजस्य को दिया। सिपन कुमार गर्ग, निदेशक(वित्त) ने कहा कि यह रिकॉर्ड निष्पादन ठोस वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनगत उत्कृष्टता के मध्य बेहतर तालमेल को दर्शाता है। कमीशनिंग के पश्चात से, रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने उत्पादन निष्पादन में निरंतर नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं, जो इसके इंजीनियरिंग डिजाइन की सुदृढ़ता, उच्च अनुरक्षण व्यवस्था और स्थायी प्रचालनगत उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि प्रचालनगत उत्कृष्टता और देश के लिए स्थायी ऊर्जा उत्पादन के प्रति एसजेवीएन की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

हरीश दुहान ने डब्ल्यूसीएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला

नई दिल्ली। हरीश दुहान ने शनिवार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सीएमडी के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें डब्ल्यूसीएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी 1 फरवरी से प्रभावी होगी, प्रारंभिक अवधि तीन महीने के लिए या अगले आदेश तक जारी रहेगी। दुहान के पास कोयला खनन क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है



और 1989 में डब्ल्यूसीएल में अपना पेशेवर करियर शुरू किया था। उनके पास प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। अपने करियर के दौरान, दुहान ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में निदेशक (तकनीकी-संचालन) के रूप में कार्य किया है। उन्होंने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें निगाही परियोजना में एरिया जनरल मैनेजर और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग में जनरल मैनेजर शामिल हैं। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं, डिजिटलीकरण पहलों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञता के लिए वे व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से डब्ल्यूसीएल की परिचालन क्षमता में और मजबूती आने और टिकाऊ एवं भविष्य के लिए तैयार विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। दुहान नागपुर स्थित डब्ल्यूसीएल के मुख्यालय पहुंचे, जहां कंपनी के निदेशक मंडल, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और महाप्रबंधकों एवं विभागीय प्रमुखों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कोयला उत्पादन, उत्पादकता और अन्य संबंधित परिचालन मामलों पर केंद्रित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

30 **प्राइम स्पेक्टेटर (मासिक पत्रिका) फरवरी 2026, दिल्ली**

कोटा रवि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर के सीएमडी नियुक्त



नई दिल्ली। भारत की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने आधिकारिक तौर पर कोटा रवि को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया है। उन्होंने यह जिम्मेदारी एक ऐसे समय में संभाली है जब भारत रक्षा क्षेत्र में वैश्विक हब बनने की ओर अग्रसर है। श्री रवि के पास एयरोस्पेस क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। सीएमडी बनने से पहले, वह एचएएल में निदेशक (संचालन) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने विमानों के विनिर्माण, डिजाइन और रखरखाव में कई जटिल परियोजनाओं का

नेतृत्व किया है, जिससे उन्हें जमीनी स्तर की गहरी समझ है। उनके कार्यकाल में एचएएल का मुख्य फोकस 'आत्मनिर्भर भारत' को सशक्त करना होगा। उनके नेतृत्व में एलसीए तेजस एमके 1ए, एमके2 और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एएमसीए जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही, वे निर्यात बाजार में एचएएल की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देंगे। श्री रवि का चयन पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) ने इंटरव्यू लिया था। जिसके बाद पीईएसबी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए कोटा रवि के नाम की सिफारिश की है।

आरईसी, पीएफसी बोर्ड ने मर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दी



नई दिल्ली। आरईसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सेक्टर में स्केल और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार, दोनों पब्लिक सेक्टर की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के प्रस्तावित मर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के तहत नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए विजन पर जोर दिया, जिसमें क्रेडिट वितरण और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए साफ लक्ष्य रखे गए हैं, और कहा कि पब्लिक सेक्टर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में स्केल हासिल करने और एफिशिएंसी बेहतर बनाने की दिशा में पहले कदम के तौर पर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन के रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव दिया गया है। 6 फरवरी 2026 को, पीएफसी और आरईसी के बोर्ड ने कहा कि प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग में लागू कानूनों और रेगुलेटरी जरूरतों के अनुसार एक विस्तृत मर्जर योजना तैयार करना शामिल होगा। योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, जरूरी मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। अपनी फाइलिंग में, आरईसी और पीएफसी (संशोधित फाइलिंग में) दोनों ने यह सुनिश्चित किया है कि मर्जर के बाद बनी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक "सरकारी कंपनी" के रूप में ही वर्गीकृत रहेगी। मर्जर स्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन रोडमैप और लागू करने की समय-सीमा के बारे में और जानकारी मंजूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयर की जाएगी। पीएफसी के पास वर्तमान में आरईसी में 52.63 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी है, जो 2019 में भारत सरकार की आरईसी में शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण के बाद हासिल हुई है। प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.

सरकार ने इंडिया एनर्जी स्टैक टास्कफोर्स ने वर्जन 0.3 स्ट्रेटेजी और आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स जारी किए



नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय ने इंडिया एनर्जी स्टैक आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स के वर्जन 0.3 को जारी करने की घोषणा की, जो भारत के पावर सेक्टर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक और कदम है। इंडिया एनर्जी स्टैक का मकसद एक कॉमन डिजिटल फ्रेमवर्क बनाना है जो अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स – जैसे यूटिलिटीज, सिस्टम ऑपरेटर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इनोवेटर्स और कंज्यूमर्स वृ को शेयर्ड स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से डेटा एक्सचेंज करने और इंटरैक्ट करने में मदद करे। इस तरीके का मकसद एनर्जी इको.

सिस्टम में कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है। अपडेटेड वर्जन 0.3 डॉक्यूमेंट्स में, अलग-अलग डेवलपमेंट और कंसल्टेशन के जरिए फ्रेमवर्क को डिजाइन, टेस्ट और बेहतर बनाने के लिए चल रहे काम को दिखाया गया है। आईईएस पहल को इकोसिस्टम कोलेबोरेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में नेशनल रोलआउट के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा भरोसेमंद, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर-रेडी पावर सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके। खास बात यह है कि इंडिया एनर्जी स्टैक से कंज्यूमर्स और प्रोज्यूसर्स को एनर्जी इकोसिस्टम में ज्यादा कंट्रोल और हिस्सेदारी देकर फायदा होने की उम्मीद है। सहमति पर आधारित डेटा शेयरिंग और इंटरऑपरेबल डिजिटल सर्विसेज के जरिए, कंज्यूमर्स बेहतर एनर्जी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, ऑफर की तुलना कर सकते हैं, और डिमांड रिस्पॉन्स या ईवी चार्जिंग जैसे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोज्यूसर्स, जो बिजली बनाते और इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा आसानी से सरप्लस एनर्जी को मोनेटाइज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन वेरिफाई कर सकते हैं, और एनर्जी मार्केट में शामिल हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर भरोसेमंद मेजरमेंट, वेरिफिकेशन और सेटलमेंट को मुमकिन बनाकर, यह फ्रेमवर्क घरों, बिजनेस और कम्युनिटी ग्रुप्स को भरोसे के साथ हिस्सा लेने और अपने एनर्जी ऑप्शन से आर्थिक रूप से फायदा उठाने में मदद कर सकता है। वर्जन 0.3 का रिव्यू करने वाली मीटिंग में टास्कफोर्स के चेयरमैन डॉ. राम सेवक शर्मा (पूर्व डायरेक्टर जनरल, UIDAI, पूर्व सीईओ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, पूर्व चेयरमैन, ट्राई), प्रदीप कुमार पुजारी (वाइस चेयर, डिस्टिंग्विशड फेलो, FSR ग्लोबल, पूर्व चेयरमैन, बृहत् पूर्व सेक्रेटरी, पावर); प्रमोद वर्मा (को-फाउंडर, FIDE, पूर्व चीफ आर्किटेक्ट, आधार), अभिषेक रंजन (CEO, BRPL), विक्रम गंडोत्रा (प्रेसिडेंट-इलेक्ट, IEEMA), विक्रम ढाका (रिप्रेजेंटेटिव, MNRE), स्वेता रवि कुमार (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, FSR ग्लोबल), डॉ. राहुल टोंगिया (सीनियर फेलो, CSEP), रेजी पिल्लई (प्रेसिडेंट, ISGF), और प्रणव तायल (डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर) और दूसरे जाने-माने लोग शामिल हुए। इस पहल को आरईसी लिमिटेड नोडल एजेंसी के तौर पर चला रही है, जो विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है और नॉलेज पार्टनर के तौर पर एफएसआर ग्लोबल इसका सपोर्ट कर रहा है। इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) प्रोजेक्ट जुलाई 2026 तक पूरा होने वाला है। प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.

इंडियन ऑयल ब्राजील से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाएगा

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉर्प ने रूसी तेल आयात कम करने के बाद, अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनैशियल ईयर में ज्यादा ब्राजीलियाई कच्चा तेल खरीदने का वादा किया है, एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि रिफाइनर, जिसने हाल ही में कोलंबिया और इक्वाडोर से कच्चे तेल के पहले कार्गो खरीदे हैं, आने वाले फाइनैशियल ईयर में टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने कच्चे तेल का 50 प्रतिशत खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के कारण उन्होंने नाम न बताने का अनुरोध किया। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रियायती रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों से पैदा हुई चुनौतियों के कारण आखिरकार भारतीय रिफाइनरों को मिडिल ईस्ट सहित अन्य स्रोतों से आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय रिफाइनर वेनेजुएला के कच्चे तेल के आयात पर विचार कर रहे हैं, जिसे विटोल और ट्रैफिगुरा अमेरिकी आदेशित बिक्री के तहत पेश कर रहे हैं। आईओसी के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ट्रेडर वेनेजुएला के कच्चे तेल को दुबई कोड्स पर 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर दे रहे हैं, जो आकर्षक नहीं है क्योंकि रिफाइनर रूसी तेल ऑफर के समान 7 से 8 डॉलर की ज्यादा छूट चाहते हैं।

बीपीएससीएल सीईओ एस.के.व्यास ने दामोदर वैली को 40 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा



कोलकाता। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को डीवीसी टावर्स में बोकारो पावर स्प्लाइ कंपनी लिमिटेड (बीपीएससी.एल) से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 40 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त हुआ। बीपीएससीएल के सीईओ सुधीर कुमार व्यास, उनके साथ बीपीएससीएल के सीएफओ पंकज कुमार माजी और बीपीएससीएल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख नीरज सिन्हा ने डीवीसी के कार्यकारी निदेशक (वित्त) सदानंद मुखर्जी को चेक सौंपा। इस अवसर पर डीवीसी के सदस्य (वित्त) अरूप सरकार भी उपस्थित थे। बीपीएससीएल, डीवीसी और एसएआईएल का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों कंप. नियों की समान हिस्सेदारी है, जो एक मजबूत साझेदारी और निरंतर वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्ट्रेटर डेस्क.

आरईसी महाप्रबंधक (वित्त) अवनीश भारती, प्रतिष्ठित आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित



नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त) अवनीश कुमार भारती को ट्रेजरी प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, नेतृत्व क्षमता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल फाइनेंस कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2026 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस अवसर पर अवनीश कुमार भारती को यह सम्मान पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा देश के वित्त, बैंकिंग एवं नीति निर्माण क्षेत्र से जुड़े अनेक वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड को वित्तीय क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, जो ट्रेजरी एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता, दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाले पेशेवरों को प्रदान किया जाता है। आरईसी लिमिटेड निरंतर पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा देश के वित्तीय एवं ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने वाली पहलों का निरंतर समर्थन करता रहेगा।

प्राइम स्पेक्ट्रेटर (मासिक पत्रिका) फरवरी 2026, दिल्ली 33

सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी

बारामती विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु



राजकुमार केशरवानी महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार (62) ने शनिवार 31 जनवरी को मुंबई में एक समारोह में महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकीं सुनेत्रा को यहां लोक भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले दिन में, उन्हें औपचारिक रूप से राकांपा विधायक दल का नेता चुना गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार नीत राकांपा के घटक वाली श्महायुति सरकार में अजित पवार उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। उनकी 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुनेत्रा पवार जब शपथ लेने के लिए उठीं तो 'अजित दादा अमर रहें' जैसे नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल सहित अन्य लोग समारोह में उपस्थित थे। सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे जय पवार और उनकी पत्नी भी शपथग्रहण समा-

रोह में मौजूद थीं। सुनेत्रा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। उनके बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है जो उनके पति अजित पवार के निधन से खाली हुई है। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली और चर्चाओं से दूर रहने वाली सुनेत्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती में अपनी ननद और मौजूदा राकांपा (शप) की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सुले से हारने के बाद, वह राज्यसभा के लिए चुनी गईं। सुनेत्रा पवार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राकांपा को एकजुट रखना और भाजपा तथा एकनाथ शिंदे

के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन की राजनीति को संभालना है। लेकिन उनकी तात्कालिक चुनौती यह तय करना होगा कि राकांपा का राकांपा (शप) के साथ बहुप्रतीक्षित विलय को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

हम अजित पवार की विरासत और आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे: सुनेत्रा पवार
महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने शनिवार को कहा कि वह अपने दिवंगत पति अजित पवार की विरासत और आदर्शों को आगे बढ़ाएंगी। सुनेत्रा ने कहा कि पति द्वारा कर्तव्य, संघर्ष और जनता के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर दी गई सीख उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच





शेक्सपियर पर एक पोस्ट में कहा कि अजित पवार ने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए समर्पित कर दिया और समाज को सार्थक जीवन जीने का मंत्र दिया। सुनेत्रा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और भीमराव आंबेडकर के आदर्शों के प्रति अडिग रहते हुए उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करके अति भावुक हूँ। नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार के असामयिक निधन से अपार दुख हुआ है, लेकिन उनके द्वारा प्रदत्त मूल्य, कर्तव्य की भावना, संघर्ष करने की शक्ति और लोगों के प्रति जवाबदेही, उनके लिए हमेशा सच्चा सहारा बने रहेंगे। सुनेत्रा पवार ने न्यायपूर्ण, समतावादी और विकसित महाराष्ट्र के अजित पवार के सपने को साकार करने के लिए अटूट ईमानदारी के साथ काम करने का संकल्प लिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में महाराष्ट्र की जनता द्वारा दिखाया गया प्रेम और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने रेखांकित किया कि वह अजित पवार के विचारों को जीवित रखते हुए नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शेक्सपियर पर किए गए एक पोस्ट का जवाब देते हुए सुनेत्रा पवार ने कहा कि उनका आशीर्वाद प्रेरणा का

स्रोत है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं ने महाराष्ट्र की सेवा में एक नई जिम्मेदारी शुरू करते समय उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और सार्वजनिक कल्याण के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने के उनके संकल्प को और भी बल दिया। अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के नजदीक हुए विमान हादसे में मौत हो गई थी।

राजनीतिक नेता की साधारण पत्नी से लेकर उपमुख्यमंत्री बनने तक का सफर
महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक पवार परिवार की छत्रछाया में रहकर राजनीति में कदम रखने वाली सुनेत्रा पवार शनिवार को राज्य की पहली महिला

उपमुख्यमंत्री बन गईं। इसके साथ ही उनके पति अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा के कंधों पर आ गई है। राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार (62) का भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार में नंबर दो पर आसीन होना राकांपा के लिए भी एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। बारामती में 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में राकांपा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को शनिवार को राकांपा के विधायक दल का नेता चुना गया और शाम को उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मराठवाड़ा क्षेत्र के धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद) जिले के तेर गांव से ताल्ल.





क रखने वालीं सुनेत्रा पवार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जीवन के अधिकांश समय तक सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी थीं। उनके भाई पदमसिंह पाटिल राकांपा के वरिष्ठ नेता हैं। पिता बाजीराव पाटिल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में शामिल थे, जो हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय से पहले हुआ था। श्वाणिज्य वर्ष में पढ़ाई करने वालीं सुनेत्रा पवार को चित्रकारी, संगीत, फोटोग्राफी और कृषि में रुचि है। शादी के बाद उन्होंने काटेवाडी गांव में सक्रिय रूप से खेती शुरू की। शरद पवार ने 1999 में राकांपा की स्थापना की थी, लेकिन जुलाई 2023 में उनके भतीजे अजित पवार के भाजपा-शिवसेना महायुति सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इसके बाद अजित पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने नवंबर 2024 में महायुति गठबंधन की भारी जीत के बाद बनी देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी यही पद संभाला। सुनेत्रा पवार को उनकी वेबसाइट पर एक प्रखर पर्यावरण विद और उद्यमी बताया गया है। उच्चा. ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में पदार्पण करते हुए अपने परिवार के गढ़ बारामती से अपनी ननद और राकांपा (एसपी) की मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुप्रिया सुले से हारने के बाद वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं। उनके बड़े बेटे पार्थ 36

पवार 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव हारने के बाद राजनीति से दूर हो गए, जबकि छोटे बेटे जय एक उद्यमी हैं। एक ओर जहां अजित पवार ने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति में कदम रखा, वहीं सुनेत्रा पवार 2024 के आम चुनाव तक राजनीति से मोटे तौर पर दूर रहीं। साल 2010 में उन्होंने 'एंवाय. रनमेंट फोरम ऑफ इंडिया' (ईएफओआ. ई) की स्थापना की। ईएफओआई एक गैर-सरकारी संगठन है जो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समुदायों के लोगों के लिए काम करता है। उनके नेतृत्व में ईएफओआई ने भारत में 'इको-विलेज मॉडल' को पेश किया, जो ग्रामीण विक.।स और पारिस्थितिकी को साथ-साथ रखने का अभिनव तरीका है। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण, संकटग्रस्त प्रज.।तियों की सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और सूखा राहत अभियानों का नेतृत्व भी किया। सुनेत्रा पवार शरद पवार द्वारा स्थापित विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी भी हैं और फ्रांस में स्थित 'वर्ल्ड एंटरप्रेन्यो. रशिप फोरम' के थिंक-टैंक की सदस्य के रूप में उन्होंने सतत विकास और सामाजिक नवाचार पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने निर्मल ग्राम अभियान के तहत महाराष्ट्र के 86 गांवों में स्वयं-सहायता समूह आंदोलन का नेतृत्व किया, और बारामती के काटेवाडी गांव को 'इको-विलेज' में

बदलकर स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामुदायिक पशुपालन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया। सुनेत्रा पवार 'बारामती हा. ई-टेक टेक्सटाइल पार्क' की चेयरपर्सन भी हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने वाली एक बहु-आयामी कपड़ा निर्माण कंपनी है। इसमें 15,000 से अधिक महिलाएं कार्य करती हैं। सुनेत्रा पवार को राकांपा को एकजुट बनाए रखने, भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन समीकरण को संभाले रखने और राकांपा के दोनों गुटों के विलय के बारे में निर्णय लेने जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा।

सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा वित्त मंत्रालय, सुनेत्रा को दी ये तीन विभाग
बारामती प्लेन क्रैश हादसे में अजित पवार के निधन के बाद शनिवार (31 जनवरी) को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की कमान संभाल ली है। सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं। शपथ लेने के बाद अब उनको कई विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। सुनेत्रा को खेल एवं युवा कल्याण विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क एवं अल्पसंख्यक विभाग की जि.म्मेदारी मिली है। हालांकि वित्त विभाग जो पहले अजित पवार के पास था, वो सुनेत्रा को नहीं मिला है। सीएम देवेंद्र फडणवीस इस विभाग को अपने पास रख

‘गे। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्रालय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और दिवंगत राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग मिले हैं। प्लानिंग और फाइनेंस विभाग, जो पहले दिवंगत नेता अजित पवार के पास थे, वो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। यानी इस बार का बजट भी सीएम फडणवीस ही पेश करेंगे।

बेटे पार्थ जा सकते हैं राज्यसभा

सुनेत्रा पवार को राजनीति में बहुत अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन वे पवार परिवार की सदस्य होने के कारण राजनीति की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वह पहले सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। 2024 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। अब उपमुख्यमंत्री बनने के साथ उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जा सकते हैं।

पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार को शुभकामनाएं दीं



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर सुनेत्रा पवार को शुभकामनाएं दीं। मा. मोदी ने शंक्कश पर एक पोस्ट में कहा कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उप.

मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं, वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और दिवंगत अजितदादा पवार के विजन को पूरा करेंगी। अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष थे। शनिवार को सुनेत्रा पवार को राकांपा विधायक दल की नेता चुना गया। सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई में एक समा. रोह में महाराष्ट्र की पहली महिला उप. मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनने पर आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दीं



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनेत्रा पवार को शुभकामनाएं दीं, जो शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनीं। आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि सुनेत्रा अजित पवार को महा. राष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के कुशल नेतृत्व में जारी महाराष्ट्र की विकास यात्रा को आप नयी गति प्रदान करेंगी। उज्ज्वल कार्यक. ल हेतु अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार (62) ने शनिवार को मुंबई में आयोजित एक समारोह में महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजित

पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राक. ांपा अध्यक्ष थे। सुनेत्रा पवार को शनिवार को राकांपा विधायक दल का नेता चुना गया।

गडकरी ने मुश्किल समय में जिम्मेदारी ले लेने पर सुनेत्रा पवार की प्रशंसा की



काद उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ले लेने को लेकर सुनेत्रा पवार की शनिवार की भूरि-भूरि प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष गडकरी ने शंक्कश पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सुनेत्रा पवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। यह प्रशंसनीय है कि सुनेत्रा पवार ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता से जिम्मेदारी ले ली है। भाजपा नेता और राज्य में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र ने एक ‘अत्यंत अनुभवी उपमुख्यमंत्री’ को खो दिया है तथा उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। उन्होंने सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बाद संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार की जनता की सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि सुनेत्रा वाहिनी (मराठी में भाभी) उनकी विरासत को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगी। शेलार ने हालांकि, जल्दबाजी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की हो रही आलोचना पर कोई टिप्पणी नहीं की।

राजस्थान की युवा साध्वी की मौत पर उठ रहे हैं सवाल

एसआईटी करेगी साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच



रानू पाठक
राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की 23 वर्षीय साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार बालोतरा जिले के परेऊ गांव में समाधि के रूप में किया गया। मृतक साध्वी के पिता वीरमनाथ का दावा है कि जुकाम और गले में खराश के दौरे रान गलत इंजेक्शन दिए जाने से उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते मौत हुई है। नागौर से सांसद हनुमान बेनिवाल ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है जिसने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के लिए विसरा की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और इस मामले में अब तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है।

क्या हुआ था?

मृतक साध्वी के मामा गंगाराम ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा अजमेर से मंगलवार (27 जनवरी) देर रात जोधपुर आई थीं। अगले दिन फिर एक कथा के

लिए उन्हें अजमेर ही जाना था। उनके गले में खराश और जुकाम की शिकायत होने पर पास ही रहने वाले कंपाउंडर को बुलाया गया था। साध्वी के लगभग 42 साल के पिता वीरमनाथ ने कहा कि जोधपुर के आरती नगर में हमारे आश्रम (घर) से करीब दो सौ मीटर दूरी पर ही कंपाउंडर देवी सिंह रहता है। 28 तारीख की शाम उसने दो अलग-अलग शीशियों से दवाइयां भर कर साध्वी को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही साध्वी को बहुत तेज छींक आने लगीं और सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। इसके बाद वह दौड़ते हुए आश्रम से बाहर निकलीं और कहा कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। तबियत बिगड़ने के कारण वह गाड़ी में बैठ नहीं पा रही थीं। हम उन्हें

जोधपुर में ही प्रेक्षा अस्पताल लेकर गए। रास्ते में साध्वी ने बोला कि पापा मुझे न्याय दिलाना, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद वह कुछ नहीं बोल पाईं। वीरमनाथ के मुताबिक, जब तक वो अपनी बेटी साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने कहा कि जब प्रेम बाईसा को लेकर आए तब हमने चेक किया तो उनका बीपी और पल्स नहीं चल रहा था। साध्वी के शव का 29 जनवरी की सुबह जोधपुर के जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया था। इस दौरान मोर्चरी के बाहर हंगामा भी हुआ था। वीरमनाथ कहते हैं कि हम जांच के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहां भी पुलिस ने मेरी सहमति मांगी मैंने दी है। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया था। जबकि, मैं तो पुलिस को सहयोग कर रहा था।

कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा

साध्वी प्रेम बाईसा का जन्म बालोतरा के परेऊ गांव में हुआ था। वह अपने माता-पिता की अकेली संतान थीं। साध्वी की उम्र लगभग पांच वर्ष रही होगी जब उनकी माता का निधन हो गया था। उनके मामा गंगाराम कहते हैं कि बचपन से ही प्रेम बाईसा का धर्म के प्रति झुकाव था। उनके अनुयायी और





कथा वाचन सुनने वाले हजारों-लाखों लोग आज दुखी हैं। साध्वी के शिष्य 42 साल के रेवतराम परेऊ गांव में साध्वी के समाधि स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि मैं करीब 12 साल से साध्वी जी का शिष्य हूँ। उनका व्यवहार बहुत अच्छा और नम्र था। किसी भी परिस्थिति में वह सहज रहती थीं। वह इतनी अच्छी कथा सुनाती थीं कि श्रोताओं की आंखें नम हो जाती थीं। वीरमनाथ बताते हैं कि छह साल की उम्र से ही वह प्रवचन करने लगी थीं और आठ साल की उम्र में उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था। वह कथा और सत्संग करने के साथ ही जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष की पढ़ाई भी कर रही थीं। वीरमनाथ आगे कहते हैं कि उनके ऊपर बड़े संत महात्माओं और शंकराचार्य का भी आशीर्वाद था। वह हमेशा कहती थीं कि मुझे प्रकृति ने योगी बनाकर भेजा है, मैं हर परीक्षा और कठिन परिश्रम के लिए तैयार हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं दुखी प्राणियों की मदद कर सकूँ और सनातन का प्रचार सकूँ। गंगाराम कहते हैं कि प्रेम बाईसा ने जोधपुर में अपना खुद का आश्रम साधना कुटीर स्थ.

पित किया था। यहां वह भक्तों के साथ धार्मिक कार्यक्रम करती थीं। उनके भजन और कथाओं का प्रचार सोशल मीडिया से होता था और हजारों की संख्या में भक्त उनके भजन और सत्संग सुनने के लिए आते थे। वह प्रदेश और देश में कई जगह कथा वाचन करने जाती थीं और लाखों की संख्या में उनके भक्त थे।

पुलिस जांच कहां तक पहुंची?

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से आहत उनके भक्त और संत महात्मा बड़ी संख्या में परेऊ गांव पहुंच रहे हैं और उनकी मौत की निष्पक्ष रूप से जांच की मांग कर रहे हैं। नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक टीवी चैनल से बातचीत में साध्वी की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अचानक पांच मिनट के अंदर एक साध्वी की मौत हो जाए तो प्रदेश यह जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या था। किसी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, यह सुसाइड था या कुछ और था यह राजस्थान जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रेम बाईसा की हत्या हुई है। मुझे लगता है, सौ फीसदी यह हत्या है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व

में एक एसआईटी का गठन किया है। एसीपी छवि शर्मा ने कहा कि हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। डॉक्टरों का फाइनल ओपिनियन आने के बाद ही जांच की राह भी तय होगी और मौत के सही कारण सामने आएंगे। साध्वी के पिता वीरमनाथ ने कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मौत होने का दावा किया है। कंपाउंडर से पूछताछ में क्या पता चला है? इस सवाल पर एसीपी शर्मा कहती हैं कि कंपाउंडर ने बताया कि नॉर्मल इंजेक्शन लगाया गया था। वह एक रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ हैं जो इंजेक्शन लगाना जानते हैं। लेकिन, क्या डॉक्टर के बिना वह इंजेक्शन लगाने के लिए अधिकृत हैं, यह हम मालूम कर रहे हैं। इलाके में अब कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एसीपी शर्मा कहती हैं, प्बालोतरा के परेऊ में बीते दिन शव की अंतिम क्रिया की गई है। पूरी तरह से शांति है और लॉ एंड ऑर्डर सामान्य है। डीसीपी वेस्ट जोधपुर विनीत बंसल ने कहा कि विसरा सैपल हमें मिल गए हैं। हम उनको लैब में भेजने की प्रक्रिया कर रहे हैं। विसरा जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण सामने आएंगे।

बीते साल हुआ था विवाद

साल 2025 में साध्वी का अपने पिता को गले लगाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस दौरान साध्वी ने वीडियो के आधार पर एक युवक पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। क्या उस वीडियो का भी साध्वी की मौत से कोई संबंध हो सकता है? इस सवाल पर डीसीपी बंसल कहते हैं कि उस प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया था। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसका इस प्रकरण से कोई संबंध हो सकता है या नहीं। साध्वी की मौत के करीब तीन घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट भी किया गया था। इस पर विवाद बढ़ने पर वीरमनाथ ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही यह पोस्ट शेयर करवाया था। डीसीपी बंसल स्पष्ट करते हैं कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।

हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर अपने आशियाने बचाने की लड़ाई जीती



समस्याओं का सामना करना पड़ा?

राजकोट शहर (पूर्व) के मामलतदार (एक तरह के राजस्व अधिकारी) ने पिछले साल 17 दिसंबर को लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 61 के तहत पहला नोटिस जारी किया था, जिसमें मकान मालिकों को बताया गया था कि जिस जमीन पर उनके घर बने हैं वह सरकारी जमीन है। रविशंकर गोगिया जंगलेश्वर के आमदभाई नाई और गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। उन्होंने बताया कि धारा 61 के तहत नोटिस मिलने पर, जंगलेश्वर के लोगों ने राजकोट की सिविल अदालत में एक याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें जमीन का मालिक माना जाए, क्योंकि वे उस पर तीस साल से अधिक समय से रह रहे हैं। इसके साथ ही, जंगलेश्वर के लोगों ने हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की और मांग की थी कि आगे की कार्रवाई करने से पहले जंगलेश्वर के लोगों की सुनवाई मामलतदार को करनी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने जंगलेश्वर के लोगों की याचिका स्वीकार कर ली थी और मामलतदार ने जंगलेश्वर के लोगों की सुनवाई की। लोगों ने जमीनधमकान की खरीद के दस्तावेज, बिजली के बिल और राजकोट नगर निगम को भुगतान की गई कर रसीदें प्रस्तुत करके उस जमीन पर अपना कब्जा साबित करने की कोशिश की। रविशंकर गोगिया ने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर मामलतदार ने आदेश दिया कि ये लोग जमीन के मालिक नहीं हैं। 27 जनवरी, 2026 को इस आदेश की प्रतियां आवेदकों को भेजी गईं। उसी दिन, उस आदेश को लागू करने के लिए, मामलतदार ने लैंड रेवेन्यू की धारा 202 के तहत आवेदकों को अंतिम नोटिस जारी कर उन्हें सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया। उन्हा.

गुजरात। कुछ दिन पहले गुजरात सरकार ने राजकोट शहर के जंगलेश्वर और आस-पास के इलाकों में 1358 घरों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने इस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। आजी और खोखरदडी नदियों के पश्चिमी तट पर स्थित इन घरों में सात हजार से अधिक लोग रहते हैं। प्रशासन ने उन्हें सात दिनों के भीतर घर खाली करने के लिए कहा था। उन्हें ये कहा गया था कि श्ये घर सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं और इसलिए यह सरकारी जमीन का अतिक्रमण है। जंगलेश्वर के अलावा, इसके दक्षिण में स्थित बुद्ध नगर, राधाकृष्ण नगर, नालोदा नगर और सिद्धार्थ नगर जैसे इलाकों में भी नोटिस जारी किए गए थे। यह पूरा क्षेत्र लोगों के बीच जंगलेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। इस इलाके में मिली-जुली आबादी रहती है। जंगलेश्वर क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जबकि अन्य बस्तियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। हाल ही आई इस मुश्किल को देखते हुए इलाके में रहने वाले दोनों धर्मों के लोग 'हिंदू-मुस्लिम एकता मंच'

नामक एक समूह के अधीन एक बार फिर एकजुट हुए और भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। इस मंच के लोगों ने कानूनी लड़ाई के हर चरण में यह सुनिश्चित किया कि 'हिंदू-मुस्लिम एकता की परिकल्पना' बनी रहे और दोनों धर्मों के लोग अपने अधिकारों के लिए एक साथ लड़ते हुए दिखाई दें। सोमवार को जब गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 202 के तहत स्थानीय मामलतदार की तरफ से जारी जमीन खाली करने के नोटिस को रद्द कर दिया, तो पूरे इलाके के लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में भी गए और इसी तरह हिंदू भी अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हसनशाह पीर के मकबरे पर सिर झुकाने गए। शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पिपरिया ने आपदा के दौरान जंगलेश्वर के लोगों की एकजुटता को विशाल खारे समुद्र में मीठे पानी की बूंदें बताई और कहा कि यह एक अच्छा संदेश है।

जंगलेश्वर के लोगों को किन कानूनी

‘ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल (जीआरटी) में मामलतद. 12 के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने सर. कार को एक आवेदन भी दिया जिसमें उनके मकानों को गिराए जाने की स्थिति में वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस क्षेत्र के लोगों के भूमि स्वामित्व संबंधी दावे भी राजकोट के सिविल कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर धारा 202 के नोटिस को रद्द करने और सरकार को याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की। जंगलेश्वर के लोगों की ओर से बिना किसी शुल्क के केस लड़ रहे रविशंकर गोगिया ने कहा कि विभिन्न अदालतों में याचिकाकर्ताओं की मांग यह है कि उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए जिस पर उनके घर बने हैं या उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए जाएं।

2001 के भूकंप के दौरान गठित हुआ था हिंदू-मुस्लिम एकता मंच

जंगलेश्वर में पान की दुकान चलाने वाले आमदभाई नाई बताते हैं कि पूरे जंगलेश्वर क्षेत्र में 35 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है और 65 प्रतिशत हिंदू है। वे आगे कहते हैं कि साल 2001 के कच्छ में आए भूकंप के बाद, दा.

66

सबसे पहले हम एक संगठन के रूप में ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए। हमारी लड़ाई कानूनी है और हमें देश के संविधान पर भरोसा है, हमें अदालत पर भरोसा है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हिंदू याचिका अलग होगी और मुस्लिम याचिका अलग। हम भाईचारे को मानते हैं, इसलिए हमने अदालत में एक साथ याचिका दायर की।

आमदभाई

हिंदू-मुस्लिम एकता मंच के सदस्य

‘नों धर्मों के लोग शहिंदू-मुस्लिम एकता मंच नामक एक समूह के तहत एकजुट हुए और कई तरह के सामाजिक कार्य करते थे। यही एकता घर गिराए जाने का नोटिस मिलने पर बहुत काम आई। आमदभाई ने कहा कि हम साठ वर्षों से साथ रहते हैं, लेकिन शहिंदू-मुस्लिम एकता मंच का पहला विचार हमारे मन में तब आया जब 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में भूकंप आया और कई गरीब लोगों को भारी नुकसान हुआ। तब हमने तय किया कि हमें एक शहिंदू-मुस्लिम एकता मंच बनाना चाहिए और जहां भी पीड़ित लोग हों, वहां राहत पहुंचाना



हमारा दायित्व है। हमें मानवता दिखानी है।।। उस समय केवल एक ही संदेश था, किसी का नाम नहीं, किसी को कोई पद नहीं, बस हिंदू-मुस्लिम एकता मंच। आमद भाई आगे कहते हैं कि दिसंबर में पहला नोटिस मिलने के बाद इस समूह के सदस्य एक बार फिर सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एक संगठन के रूप में हाई कोर्ट में और जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए। हमारी लड़ाई कानूनी है और हमें देश के संविधान पर भरोसा है, हमें अदालत पर भरोसा है। हमने सभी सरकारी दस्तावेज इकट्ठा किए, जब याचिका दायर करने की बात आई, तो हम कभी अलग से नहीं कर सकते। हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हिंदू याचिका अलग होगी और मुस्लिम याचिका अलग हो। हम भाईचारे को मानते हैं, इसलिए हमने अदालत में एक साथ याचिका दायर की।

एक याचिकाकर्ता हिंदू है और एक याचिकाकर्ता मुस्लिम

राजकोट की सिविल कोर्ट में लालाभाई मादाकिया के नेतृत्व में भूमि के स्वामित्व का दावा किया गया था और अन्य मुस्लिम धर्म के लोग एक तरह से सह-आवेदक बन गए हैं। धरमशी भोजाविया सहित हिंदू लोगों और आमद. भाई के नेतृत्व में अन्य मुसलमानों ने 8

66

याचिकाकर्ताओं ने जीआरटी में मामलतदार के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने सरकार से मकानों को गिराए जाने पर वैकल्पिक आवास का अनुरोध भी किया, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस क्षेत्र के लोगों के भूमि स्वामित्व संबंधी दावे भी राजकोट के सिविल कोर्ट में लंबित हैं. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया.

रविशंकर गोगिया

याचिकाकर्ताओं के वकील





11 मार्च 2022 के नोटिस के खिलाफ आवेदन दायर किया। इसी तरह, राधाकृष्णनगर में पान की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण भाई जमोड के नेतृत्व में कुछ मुसलमानों ने एक और याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। राधाकृष्णनगर में किराने की दुकान चलाने वाले बावभाई आहीर के नेतृत्व में दोनों धर्मों के लोगों ने मामलतदार के आदेश के खिलाफ जीआरटी में अपील दायर की है। आमद भाई के वकील रवि गोगिया और आनंद गोगिया हैं, जबकि लक्ष्मणभाई के वकील एमआर सैयद हैं। लक्ष्मणभाई का कहना है कि विभिन्न अदालतों में मुख्य याचिकाकर्ता कौन होगा, यह तय करने के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता मंच की बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के लोग, हिंदू और मुसलमान, एक साथ आए और फैसला किया कि भाई, एक याचिकाकर्ता हिंदू समुदाय से होना चाहिए और एक याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इस समूह को शिक्षक इरफान भाई कुरैशी और कांग्रेस नेता हारुन सोरा भी सलाह दे रहे थे। हारुन सोरा साल 2000 में जंगलेश्वर से राजकोट नगर निगम में पार्षद चुने गए थे।

हिंदू-मुस्लिम एकता मंच ने क्या काम किया?

आमद भाई कहते हैं कि आम दिनों में भी एकता मंच के लोग काम करते रहते हैं। उनका कहना है कि कुछ साल पहले तक इस समूह के सदस्य मामूली कीमत पर लोगों को दवाइयां देते थे। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में दा. 'नों धर्मों के लोग सामूहिक विवाह में एक-दूसरे की मदद करते हैं, और साल 2017 में, इस समूह के सदस्यों ने आजी और खोखरदडी नदियों में भाई बाढ़ के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए काम किया था। आमद भाई आगे कहते हैं, जब कोविड-19 का दौर आया तब भी हिंदू-मुस्लिम एकता मंच ने काम किया। अब एक बार फिर सर. कार की तरफ से हम पर संकट ढाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एकता मंच जंगलेश्वर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता रहा है। आमद भाई आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने इस इलाके में जंगलेश्वर के नाम पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की योजना बनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाया कि जंगलेश्वर को 202 का नोटिस जारी कर उसे गिरा दिया जाए। लेकिन हमने 1954, 1964 से दिए गए टैक्स की रिसीप्ट दी। सरकार को इसकी जानकारी थी। हिंदू-मुस्लिम एकता मंच ने फैसला किया कि हमें पूरी तरह संयम बरतना होगा, किसी को भी कानून अपने

हाथ में नहीं लेना है। आपको किसी भी अधिकारी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना है। हम गरीब लोगों के घरों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

जंगलेश्वर का हिंदू-मुस्लिम एकता मंच एकता का प्रतीक है

इसी इलाके में रहने वाले मयूर लावडिया नाम के एक कारोबारी का कहना है कि 37 साल में उन्होंने जंगलेश्वर में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं देखे। उन्होंने कहा कि सालों पहले, जब मुहर्रम के लिए ताजिया बनाया जाता था, तो हर कोई उसमें श्रीफल (नारियल) की शुभ आहुति देने जाता था और नवरात्रि के समय मुस्लिम लोग भी हमारी पूजा में शामिल होते थे। कल का दिन (सोमवार) इसका एक बड़ा उदाहरण है। मुस्लिम भाई जंगलेश्वर क्षेत्र के सभी मंदिरों में गए और यहाँ के सभी हिंदू हसनशाह पीर की दरगाह पर गए। हमारी ऐसी मानसिकता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा नहीं हुआ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कहीं न हो। मकसूद चावड़ा नामक एक नेता ने कहा कि जंगलेश्वर का शहिदू-मुस्लिम एकता मंच एकता का प्रतीक है। उनका मानना है कि यह लड़ाई इसलिए सफल हुई क्योंकि हिंदू और मुसलमान, सभी समुदाय एक मंच पर आए और गंगा-यमुनी तहजीबको आज हमारे क्षेत्र ने सार्थक करके दिखा दिया है। मुझे गर्व है कि मेरे क्षेत्र ने देश को वही एकता दिखाई है जो अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखी थी। सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पिपरिया ने जंगलेश्वर के लोगों को उनकी कानूनी लड़ाई में सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मेरी राय में, जंगलेश्वर में न तो हिंदू रहते हैं और न ही मुसलमान। वहाँ इंसान रहते हैं। इंसान मुश्किल समय में एक-दूसरे की मदद करते हैं। जब देश में हिंदू-मुस्लिम संघर्ष का माहौल है, तब जंगलेश्वर के लोग एक विशाल खारे समुद्र में मीठे पानी की बूंदों की तरह हैं।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की

विपक्ष ने एनडीए सरकार पर किसानों के हितों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया

मुनील नेगी

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

वर्तमान में सबसे चर्चित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल और भारतीय राष्ट्रीय समावेशी लोकतांत्रिक गठबंधन के घटक दल इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे स्पष्ट आत्मसमर्पण बता रहे हैं। ट्रंप कई मौकों पर भारत और उसके नेतृत्व को धमकाते रहे हैं, खासकर तब से जब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और कूटनीतिक रूप से रूस और चीन का साथ दिया, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका के विरोधी रहे हैं।

कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र रहे और इसके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाताओं से अच्छा समर्थन प्राप्त करके मोदी के चुनाव के दौरान उनके समर्थन को स्वीकार किया था, प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकों, यूक्रेन युद्ध को कम करने के प्रयासों और अंततः रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने के बाद भारतीय नेतृत्व के खिलाफ हो गए।

इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए कठोर रुख और चीन और रूस के साथ खुले तौर पर किए गए उनके व्यवहार दृष्टि जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल का जवाब न देना भी शामिल है — ने अंततः ट्रंप को भारत के प्रति नरम रुख अपनाने और टैरिफ को पहले 50: से घटाकर 25: और अब 18: करने के लिए विवश कर दिया। हालांकि, भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं, खाद्य और कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जिनमें सूखे अनाज, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं, पर एक प्रतिशत भी टैरिफ न लगाने या टैरिफ में उल्लेखनीय कमी करने पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की।

जहां सत्ताधारी दल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कार्यान्वयन को



ऐतिहासिक बताते हुए गर्व से अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और वामपंथी दल, प्रधानमंत्री पर साम्राज्यवादी अमेरिका के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने और भारतीय किसानों की पहले से ही टूटी हुई कमर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

किसान नेता और ग्राम स्वराज कार्यकर्ता डॉ. देवेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई यह रियायत भारत के अधिकांश कृषि उत्पादों और कृषि बाजार पर अमेरिका का एकाधिकार स्थापित करने के समान होगी, जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, जिन्हें हमारी रीढ़ की हड्डी माना जाता है।

किसान नेता और ग्राम स्वराज कार्यकर्ता डॉ. योगेंद्र यादव ने कहा कि अमेरिका को दी गई यह रियायत भारत के अधिकांश कृषि उत्पादों और कृषि बाजार पर अमेरिका का एकाधिकार स्थापित करने के समान है, जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, जिन्हें हमारी रीढ़ की हड्डी माना जाता है।

विपक्षी नेताओं ने पूछा कि डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ मात्र 3: क्यों था और अब मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे 25: से बढ़ाकर 18: क्यों कर दिया गया है?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के मसौदे के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) और भारत पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार के संबंध में एक अंतरिम समझौते (अंतरिम समझौता) के ढांचे पर सहमत होने की घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार ढांचा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन किया जाएगा।

अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जो पारस्परिक हितों पर आधारित संतुलित व्यापार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने खुले तौर पर सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्प.।दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त करने या कम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सूखे अनाज (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और



स्पिरिट आदि शामिल हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह पूर्ण आत्मसमर्पण के समान है।

हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 (बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी माल व्यापार घाटे में योगदान देने वाली व्यापार प्रथाओं को सुधारने के लिए पारस्परिक टैरिफ के साथ आयात को विनियमित करना), संशोधित रूप में, भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं, और अंतरिम समझौते के सफल समापन के अधीन, 5 सितंबर, 2025 के कार्यकारी आदेश 14346 (पारस्परिक टैरिफ के दायरे को संशोधित करना और व्यापार और सुरक्षा समझौतों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना करना), संशोधित रूप में, संरक्षित भागीदारों के लिए संभावित टैरिफ समायोजन अनुलग्नक में पहचानी गई वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर पारस्परिक टैरिफ हटा देगा, जिसमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जे शामिल हैं।

इस प्रारूप में कुछ रियायतों का आश्वासन दिया गया है, हालांकि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाए गए टैरिफ को भी हटा देगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को दूर करने के लिए 8 मार्च, 2018 के उद्घोषणा 9704 (संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्यूमीनियम के आयात को समायोजित करना), संशोधित रूप में 8 मार्च, 2018 के उद्घोषणा 9705 (संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के आयात को समायोजित करना), संशोधित रूप में और 30 जुलाई, 2025 के

उद्घोषणा 10962 (संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे के आयात को समायोजित करना) में पाए गए हैं। इसी प्रकार, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए अधिमान्य टैरिफ दर कोटा प्राप्त होगा, जो 17 मई, 2019 के उद्घोषणा 9888 (संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के आयात को समायोजित करना) में उल्लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को समाप्त करने के लिए लगाए गए टैरिफ के अधीन होगा, जैसा कि संशोधित किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल अवयवों की अमेरिकी धारा 232 जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भारत को जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और अवयवों के संबंध में वार्ता के माध्यम से समाधान प्राप्त होंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपने-अपने हित के क्षेत्रों में निरंतर आधार पर अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए और इस व्यापार समझौते के खिलाफ बोलते हुए, भारत के घटक दलों के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में एक विशाल बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को “जाल का सौदा” बताया गया था।

समझौते का विरोध कर रहे सांसदों ने कहा कि उन्हें इस समझौते के बारे में न तो विश्वास में लिया गया और न ही इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसकी जानकारी दी गई। वे एनडीए सरकार, समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे और भारत-अमेरिका समझौते के कड़े आलोचक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर एपस्टीन फाइलों में सामने आए दस्तावेजों और नामों के मद्देनजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने कहा, प्सच तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी परेशान थे क्योंकि उनसे जुड़े मामले एपस्टीन फाइलों में सामने आए थे। इसी वजह से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक ऐसा व्यापार समझौता कर लिया जिसने भारत भर में हमारे किसानों और कृषि समुदाय के हितों की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी। एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए और इस व्यापार समझौते के खिलाफ बोलते हुए, भारत के घटक दलों के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में एक विशाल बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को “जाल का सौदा” बताया गया था। समझौते का विरोध कर रहे सांसदों ने कहा कि उन्हें इस समझौते के बारे में न तो विश्वास में लिया गया और न ही इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसकी जानकारी दी गई। वे एनडीए सरकार, समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे और भारत-अमेरिका समझौते के कड़े आलोचक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर एपस्टीन फाइलों में सामने आए दस्तावेजों और नामों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने कहा, प्सच तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी परेशान थे क्योंकि उनसे जुड़े मामले एपस्टीन फाइलों में सामने आए थे। इसी वजह से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक ऐसा व्यापार समझौता कर लिया जिसने अखिल भारतीय स्तर पर हमारे किसानों और कृषि समुदाय के हितों की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी।”

लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक स्थगित होते ही और प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष पर तीखे हमले के बाद, पूरा विपक्ष मकर द्वार पर इकट्ठा हो गया और “तनशाही नहीं चलेगी” “नरेंद्र मोदी ने समर्पण किया” “लोकतंत्र की हत्या बंद करो” आदि के नारे लगाए। प्रियंका गांधी और बजट सत्र तक निलंबित सभी सांसदों ने संसद परिसर में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और इसे “जाल का सौदा” करार दिया।

गाड़ी में सफर के दौरान उल्टी आना मतलब मोशन सिकनेस है बीमारी



गाड़ी में सफर के दौरान उल्टी की शिक. रियत बहुत आम है। मेडिकल भाषा में इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। आखिर सफर के दौरान ऐसा क्यों होता है। दिमाग, आँख और शरीर के संतुलन का इससे क्या संबंध है। क्या इससे बचा जा सकता है।

मोशन सिकनेस क्या है?

मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सफर के दौरान व्यक्ति को चक्कर, उल्टी, सिर दर्द या बेचौनी से जूझना पड़ता है। यह समस्या ज्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज या हवाई यात्रा के दौरान होती है। कुछ लोगों को यह समस्या पहाड़ी रास्तों पर ज्यादा होती है। गाड़ी में होने वाली यह परेशानी समुद्री या हवाई सफर में होने वाली परेशानी जैसी ही होती है। दिल्ली स्थित सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मोहसिन वली कहते हैं कि जब हम सफर करते हैं तो असल में उस समय दिमाग को आँखों और कानों से अलग-अलग संकेत मिलते हैं। डॉ. मोहसिन वली कहते हैं कि अगर आप कार या बस में बैठे-बैठे नीचे देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो आपकी आँखें दिमाग को बताती हैं कि आप हिल नहीं रहे हैं। लेकिन कानों के अंदर मौजूद संतुलन तंत्र दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है। इन संकेतों की वजह से शरीर

को लगता है कि कोई जहरीली चीज आपके अंदर चली गई है और शरीर जहर से निपटने का एक ही तरीका जानता है— उसे बाहर निकालना, यानी उल्टी करना, इससे बचने का एक तरीका है कि आप खिड़की से बाहर दूर की तरफ देखें। ऐसा करने से आँखों और कानों से आने वाले संकेत एक जैसे हो जाते हैं और तब यह परेशानी कम हो जाती है। साल 2015 में एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, जिससे हर तीन में से एक व्यक्ति प्रभावित है। साथ ही उन्होंने पाया कि यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन कब इसकी चपेट में आएगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के न्यूरोलॉजी विभाग की डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी बताती हैं कि मोशन सिकनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बना पाता। यह सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद बैलेंस ऑर्गन (वेस्टिबुलर सिस्टम) से जुड़ा होता है। उनके मुताबिक, जब हम बस, कार, ट्रेन या जहाज में सफर करते हैं, तो आँखें, कान और शरीर के दूसरे हिस्सों से दिमाग को मिलने वाली जानकारी आपस में मेल नहीं खाती। इससे बैलेंस से जुड़े रिसेप्टर्स ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसी वजह से दिमाग के कुछ हिस्से,

जैसे ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस, उत्तेजित हो जाते हैं और हमें चक्कर और उल्टी से जूझना पड़ता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो मोशन सिकनेस कान के अंदर मौजूद बैलेंस सिस्टम और शरीर की मूवमेंट को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की गड़बड़ी के कारण होती है। डॉ. त्रिपाठी कहती हैं, कि हमारे शरीर में एक खास तरह के सेंसर होते हैं, जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उनकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाते हैं।

सफर के दौरान उल्टी क्यों होती है?

सफर के दौरान उल्टी की समस्या सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को यात्रा शुरू होते ही बेचौनी महसूस होने लगती है। वहीं, कुछ अन्य लोगों में यह परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है। ऊबड़-खाबड़ सड़कें, पहाड़ी रास्तों से गुजरना, गाड़ी के लगातार झटके और भीतर फैली दुर्गंध भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली के मुताबिक, सफर के दौरान हमारे दिमाग में एक पलूइड होता है। जब यह पलूइड हिलता है, तो उसमें पैदा होने वाली कंपन (वाइब्रेशन) गर्दन तक पहुंचती है। गर्दन के मूवमेंट के साथ यह कंपन खोपड़ी तक जाती है। इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण मतली, चक्कर और बेचौनी जैसी

“

मोशन सिकनेस हमेशा सिर्फ सफर से जुड़ी परेशानी नहीं होती. यह कभी-कभी दिमाग की किसी बीमारी या दवाई के साइड इफेक्ट का संकेत भी हो सकती है. कुछ मामलों में मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है.

डॉक्टर मोहसिन वली

सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली



समस्याएं हो सकती हैं। जब यह असहनीय हो जाए, तो उल्टी भी हो सकती है। डॉक्टर मोहसिन कहते हैं कि इन सभी लक्षणों को मिलाकर ही मोशन सिकनेस कहा जाता है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान पेट की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। खाली पेट सफर करने वाले पेट की वेगस नर्व, जो हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है, ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और चक्कर जैसा महसूस होता है। भारी भोजन के बाद सफर करने वाले, ऐसे लोग उल्टी (वोमिटिंग) की समस्या का सामना कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि सफर से पहले हल्का खाना ही खाया जाए। मोहसिन वली बताते हैं कि मोशन सिकनेस हमेशा सिर्फ सफर से जुड़ी परेशानी नहीं होती। यह कभी-कभी दिमाग की किसी बीमारी या दवाई के साइड इफेक्ट का संकेत भी हो सकती है। कुछ मामलों में मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है। इसलिए, बार-बार सफर के दौरान उल्टी होने की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

सफर में उल्टी रोकने के लिए क्या करें और क्या नहीं

भारी भोजन से बचें

सफर से ठीक पहले ज्यादा खाना न खाएं।

खाली पेट सफर न करें

हल्का भोजन या स्नैक्स जरूर लें।

दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें

अगर जरूरी हो, तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है।

चलती गाड़ी में सोए नहीं

सोते समय संतुलन बिगड़ता है और उल्टी की संभावना बढ़ती है।

मतली महसूस होने पर तुरंत रुकें गाड़ी साइड में रोककर उल्टी करें और फिर सफर शुरू करें।

बहुत ज्यादा उल्टी को नजरअंदाज न करें बार-बार उल्टी हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

किताब या मोबाइल से ध्यान भटकने से बचें

चलते वाहन में पढ़ना मोशन सिकनेस बढ़ा सकता है।

शरीर की स्थिति स्थिर रखें

सिर, कंधे, कमर और घुटनों की हलचल कम करें।

आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें, या सामने की सीट चुनें।

संभव हो तो खुद वाहन चलाएँ।

निकोटीन से बचें

धूम्रपान करने वाले लोग उल्टी की संभावना ज्यादा होती है।

सुखद संगीत सुनें

हल्का, सुखद संगीत सुनने से मतली कम महसूस होती है और सफर आरामदायक बनता है।

क्या महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा होती है?

डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के मुताबिक, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की

तुलना में अधिक देखी जाती है। इसके पीछे कई शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना है कि महिलाओं की जीवनशैली पुरुषों से अलग होती है। यही वजह है कि यह समस्या महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलती है। इस पर डॉक्टर मोहसिन वली बताते हैं कि इसका पहला कारण ब्लड प्रेशर है। आमतौर पर पुरुषों का औसत ब्लड प्रेशर महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में मोशन सिकनेस के लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं। दूसरा कारण पोश्चरल हाइपोटेंशन है। उनके अनुसार बहुत-सी महिलाएं घर के कामकाज के दौरान लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, खासकर रसोई में। लगातार खड़े रहने से खड़ी अवस्था में ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिसे पोश्चरल हाइपोटेंशन कहा जाता है। इससे चक्कर आना, मतली और मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मोहसिन वली के मुताबिक महिलाओं के शरीर में होने वाले नियमित हार्मोनल बदलाव भी एक अहम वजह हैं। पीरियड्स के दौरान शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है। वह यह भी बताते हैं कि मासिक धर्म के दौरान अगर रक्तस्राव अधिक हो जाए, तो ब्लड प्रेशर और गिर सकता है। इससे मोशन सिकनेस की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉ. वली का कहना है कि महिलाओं का ब्रेन वॉल्यूम औसतन पुरुषों की तुलना में लगभग 150 मिलीलीटर कम होता है। उनके अनुसार इससे ब्रेन पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों का असर महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है। डॉ. मोहसिन वली के मुताबिक लो ब्लड प्रेशर, पोश्चरल हाइपोटेंशन, हार्मोनल बदलाव और शारीरिक संरचना। ये सभी कारण मिलकर महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या को अधिक आम बना देते हैं।

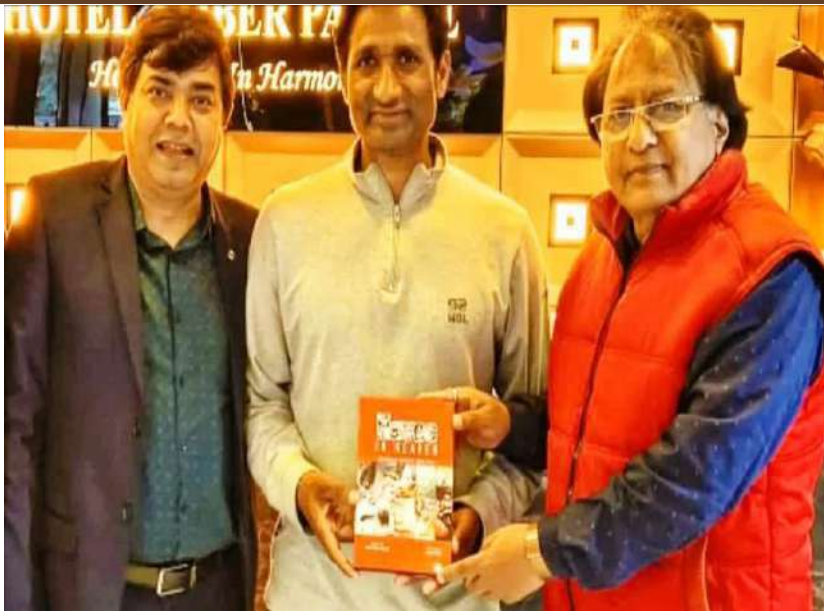


टिहरी गढ़वाल के अतीत का देव रतूड़ी, चीन का आज बहु प्रतिष्ठित शख्स बना

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया सम्मानित

हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो प्रमुख सुनील नेगी ने देव रतूड़ी से विस्तृत बातचीत की और उनके अतीत से लेकर वर्तमान तक की उपलब्धियों को जानने की कोशिश की। पेश है बातचीत के कुछ खास पहलू। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा, मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का एक ग्रामीण, जो 1998 से पहले अकेले दिल्ली आया, फर्श साफ करता था, डेयरी में काम करता था, दूध की आपूर्ति करता था, बर्तन धोता था, सुबह जल्दी उठकर डेयरी परिसर की सफाई करता था जिसमें गाय-भैंसों भी शामिल थीं, और गार्ड के रूप में भी काम करता था, लेकिन दो दशकों से अधिक समय में, अपनी कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण, प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर चीन में

रेस:



तरांधोटलों की एक श्रृंखला का मालिक बन गया, जिसमें हाल ही में गुरुग. ाम में 36 कमरों वाला एक आलीशान होटल और कई अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियां शामिल हैं। वर्तमान में चीन में एक प्रेरक और मार्शल आर्ट प्रशिक्षित फाइटर होने के साथ-साथ पचास वर्ष से कम आयु में एक प्रतिष्ठित उद्यमी भी हैं। टिहरी गढ़वाल के देव रतूड़ी को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक समा. रोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

सम्मानित किया गया।

चीन में सबसे प्रतिष्ठित भारतीय के रूप में जाने जाने वाले, जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया, देव रतूड़ी से उनके गुडगांव स्थित नए होटल 'अंबर पैलेस' के निमंत्रण पर मिलना वास्तव में एक अत्यंत सुखद अनुभव था।

वर्तमान पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रेरणास्रोत रतूड़ी चीन में रेस्तरां की एक सफल श्रृंखला चलाते हैं, जिनमें से छह विशेष रूप से शियान में हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है, जिनमें से चालीस चीनी और एक हॉलीवुड फिल्म है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित अपने साधारण गांव में साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर एक सफल व्यवसायी बनने तक का उनका जीवन सफर अद्भुत रहा है। उनका बचपन और वयस्कता चुनौतियों से भरी थी और सीमित शैक्षिक अवसरों के बावजूद, उन्होंने एक सच्चे साहसी की तरह संघर्ष किया, एक डेयरी में दूधवाले के रूप में, फिर ड्राइवर और वेंटर के रूप में काम किया।

रतूड़ी याद करते हैं: उन्हें अवसर तब मिला जब वे 1998 में चीन में एक



रेस्तरां में काम करने गए। धीरे-धीरे उन्होंने निचले स्तर से शुरुआत करते हुए एक कंपनी में महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे, जहां उनका वेतन 3 लाख 50 हजार डॉलर था। देव रतूड़ी कहते हैं कि उन्होंने चीनी भाषा को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया, उनके दिल में भारत माता और अपनी संस्कृति के लिए गहरा गर्व था। रतूड़ी ने एक अभिनव भारतीय थीम वाला फूड पवेलियन खोला, जिसमें भारतीय स्वाद और संस्कृति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया। इससे न केवल उन्हें ख्याति और प्रशंसा मिली, बल्कि उनके व्यंजनों के स्वादिष्ट स्वाद के लिए लोगों का प्यार भी मिला। जल्द ही उनका विचार और व्यवसाय चीन के कई प्रांतों में रेस्तरां की श्रृंखला के रूप में फलता-फूलता गया और उन्हें एक सफल अभिनेता और प्रशिक्षित मार्शल आर्ट और योग विशेषज्ञ के रूप में पहचान मिलने लगी। जब एक निर्देशक उनके रेस्तरां में आए तो देव को पहला मौका मिला और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से वे लगभग चालीस चीनी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। फिलहाल वे एक बड़े

बैनर की दक्षिण भारतीय हिंदी फिल्म पर भी काम कर रहे हैं, हालांकि फिल्म पूरी होने तक इसे गुप्त रखा गया है। देव चीन में एक बहुमुखी उद्यमी के रूप में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके जीवन और असाधारण उपलब्धियों पर एक अध्याय चीनी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। देव रतूड़ी ने कभी भी अपनी भारतीय और उत्तराखंडी जड़ों को नहीं भुलाया और चीन में कई उत्तराखंडियों को रोजगार दिलाने में मदद की। आज वे उत्तराखंड और भारत में सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं, इस प्रकार उस समाज को अपना योगदान दे रहे हैं जहां उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने गुरुग्राम में अपने नए होटल “अंबर पैलेस” का शुभारंभ किया है, जिसका सुंदर विषय है – मानवता में सद्भाव। होटल का डिजाइन बेहद आकर्षक है और यहाँ का भोजन वैश्विक मानकों का है। हम – मंजुल थपलियाल, सीईओ – विजन्स अहेड फाउंडेशन और अध्यक्ष – ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क और सुनील नेगी वरिष्ठ पत्रकार – ने देव रतूड़ी

के साथ तीन घंटे बिताए और उत्तराखंड और भारत में अपनी जड़ों से जुड़े सार्थक एकीकरणों पर चर्चा की। थपलियाल ने उन्हें एएमओएन के विकास के बारे में जानकारी दी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और नैतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। श्री नेगी ने उन्हें केदारनाथ और उत्तराखंड को अतीत में झकझोर देने वाली अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित अपनी पुस्तक “हैवोक इन हेवन” भेंट की। हमने मिलकर सामाजिक प्रभाव और पहाड़ी संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आपसी सहयोग पर चर्चा की। ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने वाले देव रतूड़ी ने चीन में तीन दशकों से अधिक समय तक रहते हुए बीस वर्षों तक हर मंगलवार को उपवास रखा और हर मंगलवार को बचाए गए पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने में खर्च किए। उनकी चार मंजिला होटल परियोजना निर्माणाधीन है और इसके माध्यम से वे कई स्कूलों और गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा और अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं।

आरसीबी ने दिल्ली को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग जीती

मंधाना-बोल ने 204 रन का रिकॉर्ड चेज कराया



श्वेतांक वर्मा
मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख



वडोदरा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। टीम ने गुरुवार को फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले आरसीबी ने 2024 में पहली बार डब्ल्यूपीएल जीती थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथा फाइनल हार गई। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डब्ल्यूपीएल फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया और आरसीबी को 204 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बेंगलुरु ने 2 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। यह डब्ल्यूपीएल फाइनल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज भी रहा। आरसीबी की जीत की सबसे बड़ी वजह कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल की जबरदस्त साझेदारी रही। दोनों ने 92 गेंदों पर 165 रन की साझेदारी की। मंधाना ने 87 रन की पारी खेली, जबकि जॉर्जिया वोल ने 79 रन बनाए। मैच का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा। आरसीबी को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। राधा यादव और नदीन डी क्लर्क ने पहली दो गेंदों पर दो सिंगल

लिए। इसके बाद राधा ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर्स की ओर शॉट खेला, लेकिन इस दौरान उनका बैट स्टंप से टकरा गया। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, हालांकि गिल्लियां नहीं गिरीं। इसी चौके के साथ आरसीबी ने मुकाबला जीतकर दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली की ओर से कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने 37 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उनके अलावा लौरा वोल्वार्ट ने 44 रन बनाए। शिनेल हेनरी 35 रन बनाकर नाबाद रही। लिजेल ली ने 37 और शेफाली वर्मा ने 20 रन का योगदान दिया। हालांकि दिल्ली ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन टीम फाइनल जीतने में फिर असफल रही। आरसीबी को टूर्नामेंट जीतने पर 6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली, जबकि रनरअप दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये मिले। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं सोफी डिवाइन को 5 लाख रुपये दिए गए। फाइनल मैच में शानदार बल्लेबाजी के लिए स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आरसीबी की प्लेइंग-11 में स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नदीन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली साठगरे, श्रेयांका पाटिल और लॉरेन बेल शामिल रहीं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जेमिमा रॉड्रिग्स (कप्तान), शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ट, मरीजन कैप, शिनेल हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नु मणि, चरणी और नंदनी शर्मा

शामिल थीं।

खिताबी जीत पर विराट कोहली का भावुक संदेश, दिग्गज ने ऐसे दी बधाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा विमेंस प्रीमियर लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस शानदार जीत के बाद आरसीबी के सबसे बड़े आइकन और भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर टीम की जमकर सराहना की है।

विराट कोहली का खास संदेश

आरसीबी की जीत के तुरंत बाद विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीम की फोटो साझा करते हुए लिखा, 'शहम फिर से चैंपियन बन गए हैं। आरसीबी का झंडा बुलंद रखा है और यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर आप सभी गर्व कर सकते हैं। स्मृति मंधाना, पूरी टीम और मैनेजमेंट टीम को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी इस जीत के हकदार हैं। इस पल का आनंद लें और अपने अदभुत फैसले के प्यार को महसूस करें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।' कोहली का यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो टीम के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है।

आरसीबी ने जीता तीसरा खिताब

यह जीत आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए किसी सपने से कम नहीं है। बेंगलुरु के लिए यह ट्रिपल डिलीट जैसा पल है, ऐसे में आइए जानते हैं कि आरसीबी ने पिछले तीन सालों में कितने



खिताब जीते हैं।

रिकॉर्ड रन चेज और रोमांचक अंत

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन का विशाल स्कोर बनाया था, जिसमें कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स (57), लौरा वोल्वार्ट (44) और लिजेल ली (37) की अहम पारियां शामिल थीं। लेकिन स्मृति मंधाना की 87 रनों (41 गेंद) और जॉर्जिया वॉल की 79 रनों (54 गेंद) की पारियों ने इस रिकॉर्ड लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। आरसीबी ने महज 2 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की और मुंबई इंडियंस के साथ लीग की सबसे सफल टीम बन गई।

जेमिमा के खिताब जीतने का सपना दोस्त मंधाना के हाथों ऐसे टूटा

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को जिगरी दोस्त माना जाता है और दोनों ही मुंबई से ताल्लुक रखती हैं। दोनों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी भी खेली पर जेमिमा का अपनी टीम को पहली बार चौपियन बनाने का सपना अपनी दोस्त के हाथों ध्वस्त हो गया। आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य 204 को छह विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत में स्मृति मंधाना की कप्तानी के दायित्व वाली पारी की अहमियत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दिल्ली कैपिटल्स पिछले तीन सीजनों की तरह ही एक बार फिर अपने हाथों में विजयी ट्रॉफी नहीं उठा सकी। वहीं आरसीबी ने तीन सालों में दो ट्रॉफी जीत ली है। इसमें पिछली डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी शामिल है। स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल की जोड़ी ने मैच को किसी हद तक एकतरफा बना दिया था। लेकिन 19वें ओवर में हेनरी ने पहले कप्तान स्मृति मंधाना को बोल्ट करने के बाद अगली ही गेंद पर राधा ने बाहर डाली गई गेंद पर चौका लगाने के प्रयास में गेंद को हवा उछाल दिया पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़ी मिन्नु ने कैच टपकाकर मैच को हाथ से निकाल दिया। राधा यादव का

अगर विकेट निकल जाता तो आरसीबी पर दबाव बन सकता था और कैच छूटने पर दौड़े दो रन और लक्ष्य में जुड़ जाते। राधा ने इस जीवनदान का फायदा उठाकर अगले ओवर में लगातार दो चौके लगाकर आरसीबी को दूसरी बार चौपियन बना दिया। राधा ने जब विजयी चौका लगाया तो प्रसारण में दिखा कि उनके विकेट की वेल्स गिर गई है। पर अंपायर ने रीप्ले में देखा कि वेल्स विकेटकीपर लिजेल ली का हाथ लगने से गिरी थी। कैच छोड़कर मैच हाथ से निकालने वाली मिन्नु ही दिल्ली को खेल में वापस लाने वाली थीं। उन्होंने 17वें ओवर में जॉर्जिया वॉल का विकेट निकालकर दिल्ली टीम के लड़ने की फिर से उम्मीद बंधाई। इससे उत्साहित नंदिनी शर्मा ने ऋचा घोष को कैच कराकर मैच को रोमांचक बनाया।

स्मृति मंधाना का साहस

जब किसी भी टीम के सामने 200 से ऊपर का लक्ष्य हो तो उसका दबाव में आना स्वाभाविक है। यही नहीं टीम के लिए कई अच्छी पारियां खेलने वाली ग्रेस हैरिस के जल्दी लौट जाने पर भी कभी टीम को दबाव में नहीं आने दिया। इसमें जॉर्जिया वॉल ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आते ही अपने शॉट खेलने शुरू कर दिए। इससे एक तो दिल्ली के गेंदबाजों को दबाव बनाने का मौका नहीं मिल सका। दूसरे इससे कुछ समय बाद स्मृति मंधाना को भी खुलकर खेलने का मौका मिल गया। स्मृति ने भी मैच के बाद माना कि हमारी दूसरे विकेट की मैच जिताने वाली 165 रनों की साझेदारी को बनाने में जॉर्जिया वॉल की भूमिका अहम रही। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों में 79 रनों का योगदान दिया, जिसमें 14 चौके लगाए। यह साझेदारी इस लीग की सबसे बड़ी साझेदारी है। जॉर्जिया ने अपनी इस पारी को फाइनल के लिए बचाकर रखा था। उन्होंने इससे पहले पांच मैचों में सिर्फ 91 रन बनाए थे पर फाइनल में जानदार पारी से जान डाल दी।

जीत के बाद की प्रतिक्रिया

मंधाना ने ट्रॉफी लेने से पहले कहा कि आरसीबी

के प्रशंसक दुनिया के सबसे अच्छे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, कमाल का सपोर्ट मिलता है। हमारी प्रेंचाइजी ने पिछले तीन सालों में दो ट्रॉफियां जीती हैं। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी पर हमारे गेंदबाजों, खासकर लॉरेन बेल ने कमाल की गेंदबाजी की। हमारी जीत में सपोर्ट स्टाफ का सहयोग भी बेहतरीन रहा। सभी खिलाड़ियों को उनकी भूमिका बता दी गई थी। उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि खिलाड़ियों को सिर्फ मैदान में उतरकर उस पर लागू करना था। हमारी टीम का आत्मविश्वास बहुत अच्छा था, ऐसी स्थिति में किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मंधाना के फाइनल में उतरने से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 342 रन बनाकर ऑरेंज कैप पाने की दौड़ में सबसे आगे थीं। लेकिन मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलकर अपने रनों की संख्या 377 रन तक पहुंचाकर ऑरेंज कैप को हासिल कर लिया। स्पोर्ट्स स्टार के लिए कमेंट्री कर रहे सबा करीम ने कहा कि स्मृति मंधाना भले ही अपना शतक पूरा नहीं कर सकीं पर उन्हें मैच जिताने वाली पारी खेलने के लिए बहुत बहुत बधाई।

राधा यादव विजयी रन लगाने से खुश

राधा यादव ने मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटरी के साथ बातचीत में कहा कि वह पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स टीम में शामिल थीं पर अब वह दिल्ली के खिलाफ ही विजयी रन बनाने में सफल रहीं। उन्होंने कहा कि हमें तैयार करने में टीम प्रबंधन की भूमिका अहम रही। हमें जिस चीज की जरूरत थी, उसे मुहैया कराया गया। हमें स्थितिओं के हिसाब से तैयारी कराई गई, इसका हमें फायदा मिला। तैयारी के समय हमको कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने के लक्ष्य दिए जाते थे। हर खिलाड़ी अपने कौशल के हिसाब से कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है, इसका हमें अभ्यास कराया गया। मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं देश को विश्व कप जिताऊंगी। प्रबंधन ने अभ्यास सत्र के बाद हमें थोड़े समय के लिए घूमने भेजा, इससे खिलाड़ी तरो-ताजा रहे। लिजेल ली और शेफाली वर्मा की अच्छी शुरुआत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स और वुलवार्ट के शानदार प्रदर्शन के बावजूद एक समय लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स 200 के आंकड़े को शायद ही पार कर पाए। इस स्थिति में हेनरी के विस्फोटक अंदाज में खेली गई पारी ने स्कोर को 203 रन तक पहुंचाने में मदद की। हेनरी ने मात्र 15 गेंदों में चार चौकों और दो छक्के से 35 रनों का योगदान किया। उन्होंने टीम को इस स्कोर तक पहुंचा दिया। यहां तक लक्ष्य का पीछा करने वाली कोई टीम नहीं पहुंची थी। पर कप्तान जेमिमा की पारी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कप्तानी का दायित्व निभाने वाली 37 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने आठ चौके लगाए।



With a legacy of 45+ years, NCC Limited stands among India's most trusted infrastructure conglomerates, delivering excellence across Buildings, Transportation, Water, Irrigation, Mining, Electrical (T&D), and Railways. From roads to digital highways, airports to power networks, NCC continues to shape India's growth story through innovation, sustainability, and inclusive development for a Viksit Bharat.

NCC Limited

NCC House, Madhapur, Hyderabad, Telangana 500081, India
T : +91 40 2326 8888 E : info@nccld.in W : www.ncclimited.com



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरल कंपनी)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)



ऊर्जा से प्रगति, विकास से विश्वास

- सतत खनन, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व
- देश की औद्योगिक एवं ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, भारत के कोकिंग कोल उत्पादन में अग्रणी भूमिका
- उन्नत तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक खनन
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, नागरिक सुविधाओं का विस्तार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
- झरिया मास्टर प्लान के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, कल्याण और आजीविका में सहयोग हेतु सतत प्रयास

